सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 352, नई दिल्ली । शुक्रवार, 01 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है।

03 दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक समान लीज डीड के ड्राफ्ट को दी मंजूरी

06 घातक है कैंसर पीड़ितों की संख्या

08 ब्रह्मपुर में बीजेपी की विजय रैली , राजनाथ ने कहा, ओडिशा मोदी का फोकस है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार परिवहन विभाग (सड़क सुरक्षा के लिए अग्रणी एजेंसी) द्वारा सड़क सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट समिति की समीक्षा संपन्न

संजय बाटला

नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय समिति ने अपने पत्र संख्या 04/2023/सीओआरएस दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ मेसर्स दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा और अंतिम रूप के संबंध में (मैसर्स डिम्ट्स, दिल्ली), दिल्ली राज्य से प्राप्त टिप्पणियों के आलोक पर इस संबंध में एम/एस, डीआईएमटीएस दिल्ली इस ऑडिट के बारे में एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया।

सड़क सुरक्षा हितधारकों-स्वास्थ्य, शिक्षा, दिल्ली यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (आईआरएडी) की बैठक मुख्य सचिव, सरकार की अध्यक्षता में निर्धारित 29/02/2024 को शाम 5:30 बजे मुख्य सचिव के कॉन्फ्रेंस हॉल कार्यालय, दिल्ली सचिवालय, 5वीं मंजिल, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-11002 पर संपन्न हुई।

सड़को पर सुरक्षा का सही रूप दिल्ली की जनता को दिखती है पर शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राज नेताओं भारत सरकार, उपराज्यपाल दिल्ली, मुख्यमंत्री दिल्ली, परिवहन मंत्री दिल्ली, आयुक्त एवम् विशेष परिवहन आयुक्त के साथ अन्य विभागो के अधिकारियों को नजर नहीं आते, आखिर क्यों ?

जनता अपना विचार व्यक्त करे।

MoRTH ने हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि! पिछले 9.5 वर्षों में भारत ने बनाया लगभग 92,000 किमी नेशनल हाईवे

संजय बाटला

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में लगभग 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्गों) का निर्माण करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। MoRTH सचिव अनुराग जैन के अनुसार, यह आंकड़ा आगामी महीने के आखिर तक बढ़कर 95,000 किलोमीटर हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (IRF) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, जैन ने परिवहन योजना में क्रांति लाने और दूरगामी परिवहन मॉडल विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने पर मंत्रालय की प्राथमिकता का जिक्र किया।

जैन ने अनुमानित भीड़भाड़ को पूरा करने और अगले पांच दशकों के लिए बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर संभावित यातायात चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण हैं।

एनएच पर ज्यादातर ब्लैक स्पॉट का समाधान

जैन ने खुलासा किया कि मंत्रालय ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर ज्यादातर ब्लैक स्पॉट्स की सावधानीपूर्वक पहचान की है और उनके समाधान को प्राथमिकता दी है। उन्हें मार्च 2025 के आखिर तक कम करने की योजना है।

इंफ्रास्ट्रक्चर की बदलती भूमिका

IRF के अध्यक्ष अनवर बेनाजौज ने बुनियादी ढांचा योजनाकारों, डिजाइनरों और ठेकेदारों की बदलती भूमिका पर जोर दिया। उन्हें इस क्षेत्र में दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उभरती टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और इंटेलिजेंट ट्रांस्पोर्ट सिस्टम (ITS) को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया।

सड़क बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण

IRF के अध्यक्ष एमेरिटस के के कपिला ने बढ़ती जनसंख्या बढ़ोतरी और बढ़ते शहरीकरण के रुझानों को एडजस्ट करने के लिए सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के आधुनिकीकरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने परिवहन परिदृश्य की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए मॉडर्न इक्यूप्मेंट, अत्याधुनिक तकनीकों, टिकाऊ सामग्रियों और व्यापक नीतिगत दिशानिर्देशों के इंटीग्रेशन की वकालत की।

उन्होंने कहा कि MoRTH और IRF जैसे संगठनों के सहयोगी प्रयास इनोवेशन लाने और परिवहन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि यह भविष्य की चुनौतियों के लिए लचीला

जल्द ही बसों में फिर से ड्यूटी करते नजर आएंगे मार्शल

बस मार्शलों की बहाली का बिल दिल्ली विधानसभा में पारित, फाइल पहुंची उपराज्यपाल के पास

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। नई दिल्ली। पिछले दो दिन से बस मार्शलों की बहाली को लेकर दिल्ली विधानसभा में चली तीखी बहस के बाद गुरूवार को सर्वसहमति से मार्शलों की बहाली के पक्ष में प्रस्ताव पास हो गया है।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मार्शलों की बहाली वाले प्रस्ताव के विधानसभा में सर्वसम्मति से पास होने के बाद इस की फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास हस्ताक्षर के लिए भी भेज दी गई है। सूत्रों के अनुसार इस फाइल को स्वयं परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत लेकर उपराज्यपाल निवास पहुंचे। इस विषय पर बस मार्शल संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेता मुकेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि मार्शल की बहाली से संबंधित फाइल एलजी वीके सक्सेना के आफिस में गुरूवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने पहुंचा दी है। एलजी के हस्ताक्षर होने बाद फाइल गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। उसके बाद अलग-अलग अथॉरटी के पास अनुशंसा के लिए भी भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर से चले आ रहे मार्शलो के धरना-प्रदर्शन और लंबे संघर्ष का नतीजा है।आज विधानसभा से इस पर सहमति होने के बाद फाइल मूव हो गई है। अब आगे का बेसब्री से इंतजार रहेगा की कितनी जल्दी सभी प्रक्रिया पूरी होकर मार्शल जो पिछले कई महीनों से सड़को पर सघर्ष कर रहें थे उन्हें अपनी ड्यूटी मिलेगी। मुकेश मार्शल ने अपने सभी संघर्षशील साथियो के साथ इस लड़ाई में उनका साथ देने वाले सभी नेताओ (सीएम केजरीवाल, आतीषी, सौरभ भारद्वाज, कुलदीप कुमार के साथ ही नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूडी का आभार जताया है।

दिल्ली की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति मार्शलों की बसों में अनिवार्यता और उपस्थिति के लिए रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा लोकसभा में मुद्दा उठाया था जिसका असर हुआ और दिल्ली विधानसभा में दो दिन तक चली परिचर्चा के बाद मार्शलों की बहाली को सर्वसम्मति दी गई।

जल्द ही दिल्ली में चलने वाली सभी कलस्टर सेवा, इलेक्ट्रिक सेवा और दिल्ली परिवहन की बची हुई बसों में पहले की तरह मार्शल नजर आएंगे और संघर्ष कर रहे बस मार्शलों के घरों में वापिस नोकरी मिलने पर दिवाली सा माहौल और खुशी देखने को मिलेगी।

दिनांक 29 फरवरी 2024 दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल बहाली का प्रस्ताव पारित किया। 4 महीने दिल्ली सचिवालय से लेकर राजघाट पावर हाउस तक धरना प्रदर्शन करने वाले यह बस मार्शल अपने रोजगार को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ डटे रहे जिसका नतीजा आज 29 फरवरी 2024 को दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक द्वारा बस मार्शल बहाली का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करके सीधा उपराज्यपाल सचिवालय भेजा गया जिसका लंबे समय से सभी को इंतजार था ।

बीजेपी नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर विधूड़ी द्वारा बस मार्शलों को पूरा समर्थन दिया और बस मार्शलों के साथ खड़े रहे। रामवीर विधूड़ी ने कहा था दिल्ली सरकार के पास बहुत से विभाग पद खाली पड़े हुए हैं वहां भी इनको लगाया जा सकता है क्योंकि इन बच्चों की उम्र सीमा निकल चुकी है यह सभी अब सरकारी नौकरी नहीं कर पायेंगे क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इनका समय और भविष्य अंधकार में डाल दिया है इनके बूढ़े माता-पिता उनके स्कूल के बच्चों की फीस घर के हालात ठीक नहीं है और दिल्ली के उपराज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर विधूड़ी ने इन्हे पूरा आश्वासन दिया कि हम दिल्ली के सभी 10792 बस मार्शल के साथ है और उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं जितना होगा हम बस मार्शल के रोजगार के लिए करेंगे और हमेशा बीजेपी भी साथ खड़ी है आपके। दिल्ली के उपराज्यपाल अब इस प्रस्ताव के पास होने के बाद सभी 10792 बस मार्शल और उनके परिवार की तरफ जरूर कुछ ना कुछ रोजगार का समाधान निकालेंगे जिनसे इनके परिवार का पालन पोषण चलता रहे।

पिछले छह सालों के दौरान राजधानी में बसों का बेड़ा तो बढ़ा लेकिन इनके यात्रियों की संख्या में आई 48.5 प्रतिशत की गिरावट

दिल्ली में ई-बसों की संख्या बढ़ने के साथ कम क्यों नहीं हो रहा प्रदूषण? सामने आई बड़ी वजह; जानें एक्सपर्ट्स की राय

परिवहन विशेष न्यूज

राजधानी दिल्ली में सिर्फ ई-बसों की संख्या बढ़ाने से ही दिल्ली के वायु प्रदूषण का समाधान नहीं होगा। ई-बसों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रदूषण बढ़ने की कई वजहें सामने आई है। 2017-18 की तुलना में यात्रियों की संख्या में 48.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। लचर सेवा अव्यवहारिक रूट और सड़कों पर रहने वाला जाम बसों के प्रति यात्रियों का भरोसा बढ़ने नहीं दे रहा।

नई दिल्ली। देश की राजधानी में इस समय इलेक्ट्रिक बसों की संख्या सर्वाधिक तकरीबन 1650 है। लेकिन यह भविष्य में यहां का वायु प्रदूषण घटने का संकेत नहीं है। इसके लिए जरूरी है इन बसों में यात्रियों की संख्या का भी बढ़ना। लोग जब तक निजी वाहन छोड़ सार्वजनिक परिवहन सेवा पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, प्रदूषण की स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आ पाएगा।

राजस्थान के नीमली स्थित अनिल अग्रवाल एनवॉयरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीटयूट में चल रहे सीएसई द्वारा आयोजित पर्यावरण सम्मेलन के दूसरे दिन प्रस्तुत की गई एक अध्ययन रिपोर्ट में इस संदर्भ में विस्तार से बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में दिल्ली में बसों की संख्या 5,695 थीं।

जाम की वजह से घट रहा भरोसा

जबकि मौजूदा समय में इनकी संख्या 7,582 हैं। इनमें 1650 ई-बसें भी शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ बसों में चलने वाले यात्रियों की संख्या घट रही है। 2017-18 की तुलना में यात्रियों की संख्या में 48.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। लचर सेवा, अव्यवहारिक रूट और सड़कों पर रहने वाला जाम बसों के प्रति यात्रियों का भरोसा बढ़ने नहीं दे रहा।

सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी बताती है कि ई-बसें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इन्हें लाने का मकसद तभी सफल हो सकेगा, जब लोग निजी वाहनों पर निर्भरता छोड़ इनमें सवारी करें।

रिपोर्ट में कही गई ये बड़ी बातें

रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी, कलस्टर बसों और मेट्रो में केवल 50.77 प्रतिशत यात्री सवारी कर रहे हैं। 49.33 प्रतिशत अब भी कार, आटो और दोपहिया वाहनों के सहारे हैं। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन मजबूत करने के लिए सड़कों की रिडिजाइनिंग और लास्ट माइल कनेक्टिवटी बढ़ाने के साथ-साथ और यात्रियों का भरोसा जीतने की भी जरूरत है।

परिवहन के साथ धूल भी बड़ी वजह

आईआईटी कानपुर के प्रो. मुकेश शर्मा ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजहों में परिवहन के साथ-साथ धूल भी शामिल है। धूल का कारण टूटी सड़कें और निर्माण स्थल हैं, जहां अब भी इसकी रोकथाम के पुख्ता उपाय नहीं किए जा रहे हैं।

दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी जिम्मेदार

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी आर के जेनामणि ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि मौसमी कारक भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा देते हैं। मसलन, सर्दियों में कोहरा छाने, हवा की रफ्तार कम होने और तापमान में गिरावट से एक्यूआई बढ़ जाता है तो गर्मियों में वर्षा ना होने और मानसून में कम वर्षा के चलते इसमें इजाफा हो जाता है।

TRAFFIC OFFENCES AND PENALTIES

S. No.	Offence Name	MVA	Penalty 1	Penalty 2
1	Travelling on Running Board (Passengers)	123(2)/177 MVA	500	1,500
2	Obstructive Driving (Extra Passenger on Driver Seat)	125/177 MVA	500	1,500
3	Triple Riding on two-wheeler	194C MVA	1,000	1,000
4	Drive on Footpath/Cycle Track	39(3) MVDR/177A MVA	0	0
5	Violation of Stop Sign	184 MVA	0	0
6	Offences relating to Juvenile	199A MVA	0	0
7	Plying of old age Diesel/Petrol vehicles (more than 15/10 years)	39/192/207 MVA	0	0
8	Driving in NMV lanes	115/194(1) MVA	20,000	20,000
9	Not giving way to an emergency vehicle	194E MVA	10,000	10,000
10	Disobey of lawful direction in case of an accident or damaging property	132/179 MVA	2,000	2,000
11	W/O Permit	66.1/192(A) MVA	10,000	10,000
12	Without Log Book	CMVR 85(10) 177 MVA	500	1,500
13	Smoking in the Vehicles	DMVR 86.1(5)/177 MVA	500	1,500
14	Blowing of Pressure Horn	39/192 MVA	5,000	10,000
15	Using horn in No Honking/Silence Zone	194F MVA	1,000	2,000
16	Use of Coloured Light on Motor	DMVR 97(2)/177 MVA	500	1,500
17	Excess Smoke	DMVR 99(1)(a)/177 MVA	500	1,500
18	Tinted Glass	CMVR 100.2/177 MVA	500	1,500
19	W/O Wiper	CMVR 101/177 MVA	500	1,500
20	Playing Music	DMVR 102/177 MVA	500	1,500
21	Driving without light after Sunset	CMVR 105/177 MVA	500	1,500
22	Unauthorized Use Siren	DMVR 107/177 MVA	500	1,500
23	Offence Committed by Enforcement Authority (Twice the Penalty corresponding to that an offence under the Act)	210B MVA	0	0
24	Violation of Stop Line	113(1)/177 DMVR	500	1,500
25	Jumping Red Light	184 MVA	0	0
26	Violation of Mandatory Signs (One Way, No Right Turn)	119/177 MVA	500	1,500
27	Driving without Horn	CMVR 119.1/177 MVA	500	1,500
28	Driving Left Hand Drive Without Indicator	120/177 MVA	500	1,500
29	Improper or Obstructive Parking	122/177 MVA	500	1,500
30	Travelling on Running Board(Driver)	123(1)/177 MVA	500	1,500
31	CARRYING HIGH/LONG LOAD / Protruding rods	194(1A) MVA	20,000	20,000
32	Without Fitness	56/192 MVA	5,000	10,000
33	Using high beam	112(4)(c)/177 MVA	500	1,500
34	Wrong Passing or Overtaking other Vehicles	184 MVA	0	0
35	Rear View Mirror Turned Inwards	125(2)CMVR 1989/177 MV Act	500	1,500
36	Helmet W/o strap or Strap Not tied	194D MVA	1,000	1,000
37	Defective Helmet (Not Confirming BIS)	194D MVA	1,000	1,000
38	Top Light Violation	108(1) CMVR/177 MVA	500	1,500
39	W/o Reflector	104/177 MVA ACT	500	1,500
40	Not using Seat-belt	194B MVA	1,000	1,000
41	Disobeying Lawful Directions	179 MVA	2,000	2,000
42	Conductor Without License	129/182 MVA	10,000	10,000
43	Driving without Helmet(Rider/Pillion Rider)	194D MVA	1,000	1,000
44	Carrying A passenger on Goods Vehicle	184 MVA	0	0
45	Carrying Goods on Passenger Vehicle	DMVR 84(4)/177 MVA	500	1,500
46	W/o RUPD	CMVR 124.1/190.2 MV Act.	10,000	10,000
47	W/o LUPD	CMVR 124.1/190.2 MV Act.	10,000	10,000
48	Violation of Yellow Line	119/177 MVA	500	1,500
49	Conductor Without Badge	DMVR 22(1)/177 MVA	500	1,500
50	Conductor Without Uniform	DMVR 23(1)/177 MVA	500	1,500
51	Not carrying animals as per provision 125E(2) CMVR 1989	125E CMVR/177 MVA	500	1,500
52	Smoking by Driver/Conductor	DMVR 11.2/177 MVA	500	1,500
53	Permit Violation	66(1)/192 A MVA	10,000	10,000
54	SC Violation	66.1/192(A) M.V.A	10,000	10,000
55	Plying JUGAD	39/192/207 MV Act 1988	0	0
56	Touting	93 MVA/193 MVA	0	0
57	Dangerous Goods By common carrier	3/18(1),13/18(1),14/18(1) CRA 2007	0	0
58	Driving Without License	3/181 MVA	5,000	5,000
59	Allowing Unauthorised Person To Drive	5/180 MVA	5,000	5,000
60	Use of Hand-Held Communication Devices While Driving	184 M.V.A	5,000	10,000
61	Violation of Restriction of Time (NO ENTRY)	115/194(1) M.V. Act 1988	20,000	20,000
62	Trucks carrying sand/dust without covering (No Entry)	115/194(1) M.V. Act 1988	20,000	20,000
63	Misbehavior with Police Officer	179 MVA	2,000	2,000
64	W/O Insurance	146/196 MVA	2,000	4,000
65	Driving Dangerously	184 MVA	0	0
66	W/O PUCC	115 CMVR /190(2)M.V.A	10,000	10,000
67	Driving against the authorized flow of traffic	184 MVA	0	0
68	RC Violation	39/192 MVA	5,000	10,000
69	Defective/Fancy/Not displaying Number Plate	50,51 CMVR / 39/192 MVA	5,000	10,000
70	Advertisements on Vehicle	DMVR 71.2/177 MVA	500	1,500
71	Drunken Driving	185 MVA	0	0
72	Over Speed LMV	112.1/183(1) MVA	2,000	0
73	Over Speed MMV/HTV	112.1/183(1) MVA	4,000	0

महिलाओं की स्वास्थ्य ज़रूरतों को प्राथमिकता

भारत के उपराष्ट्रपति ने महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है, जो देश की आबादी का लगभग 50% हिस्सा हैं।

घर के अंदर और बाहर दोनों जगह कार्यवाहक (Caretakers) के रूप में काम करने के बावजूद महिलाएँ सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं।

महिलाओं के लिये प्रोत्साहक और निवारक स्वास्थ्य समान रूप से महत्त्वपूर्ण है और इन पर जोर दिया जाना चाहिये।

स्वास्थ्य हस्तक्षेपों (Health Interventions) द्वारा महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

महिला और स्वास्थ्य

जन्म के समय लिंग अनुपात: UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 ने भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 910 होने का अनुमान लगाया है, जो सूचकांक के निचले स्तर पर है।

किशोरियों का स्वास्थ्य: किशोर उम्र में 70% लड़कियाँ एनीमिक होती हैं और उनकी मासिक धर्म और स्वच्छता से जुड़ी समस्याएँ अक्सर अनियंत्रित हो जाती हैं।

किशोर प्रजनन दर (AFR): संयुक्त राष्ट्र ने प्रति 1,000 महिलाओं पर 15-19 वर्ष की महिलाओं को जन्म की वार्षिक संख्या के रूप में किशोर प्रजनन दर (Adolescent Fertility Rate- AFR) को परिभाषित किया है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 के अनुसार, सर्वेक्षण किये गए 22 राज्यों में त्रिपुरा ने प्रति 1,000 महिलाओं पर 69 जन्म के साथ उच्चतम AFR दर्ज किया।

प्रति 1,000 महिलाओं पर 14 जन्म के साथ सबसे कम किशोर प्रजनन दर गोवा में दर्ज की गई।

किशोर गर्भावस्था: किशोर गर्भावस्था (Teenage Pregnancies) में लड़कियों की मृत्यु की संभावना 3 गुना अधिक होती है। महिलाओं की प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है।

भारत में प्रतिवर्ष लगभग 113 किशोर महिलाएँ गर्भधारण के कारण परिवादों (libels) के परिणामस्वरूप अपनी जान गवाँ देती हैं। इसके अलावा ऐसी मौतों की कम रिपोर्टिंग भी होती है।

प्रजनन स्वास्थ्य का मुद्दा: भारत की 70% महिलाएँ प्रजनन के दौरान कई (Reproductive Tract) प्रकार के संक्रमण से पीड़ित होती हैं, जिससे बाँझपन, गर्भपात और इसी तरह की समस्याएँ हो सकती हैं जिन्हें सामान्य माना जाता है।

मातृ मृत्यु दर: मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio- MMR) को एक निश्चित समय अवधि के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक ही समय अवधि के दौरान 1,00,000 जीवित जन्मों में होती है।

MMR वर्ष 2015-17 के 122 और वर्ष 2014-2016 के 130 के स्तर से घटकर वर्ष 2016-18 में 113 रह गई है।

महामारी के बीच महिलाएँ: जो महिलाएँ महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रही हैं, उनमें से कई की PPE किट जैसी साधारण ज़रूरतों तक पहुँच नहीं है, जो उन्हें संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

महिलाएँ, फ्रंटलाइन कार्यकर्त्ताओं के अलावा जो संक्रमित हो जाते हैं, उन्हें भी दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि माना जाता है कि उन्हें न केवल खुद की देखभाल करनी है बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों की भी देखभाल करनी होती है जो संक्रमित हैं।

यहाँ तक कि कोविड-19 से पीड़ित महिलाएँ जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके प्रवेश के दिनों की औसत संख्या उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत कम है।

स्कूल छोड़ने वालों में भी अधिकांश लड़कियाँ हैं।

महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने की सरकारी पहल

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र: भारत में लगभग 76,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्तन कैंसर, मुख का कैंसर और ग्रीवा कैंसर जैसे 5 प्रकार के स्वास्थ्य मुद्दों की स्क्रीनिंग करते हैं।

इन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिवर्ष आने वाले मरीजों की संख्या लगभग 46.4 करोड़ है। इनमें से 24.91 करोड़ यानी 53.7% महिलाएँ हैं।

किशोर हितैषी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम: राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram) पोषण, यौन प्रजनन स्वास्थ्य, पदार्थों का दुरुपयोग, गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा पर ध्यान केंद्रित करता है।

यह कार्यक्रम लेस्बियन (LESBIAN), गे (GAY), बाईसेक्सुअल (BISEXUAL), ट्रांसजेंडर (TRANSGENDER) और क्यूर (Queer) सहित सभी किशोरों तक पहुँचने पर ध्यान केंद्रित करता है।

सहायक नर्स मिडवाइफ: सहायक नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwife- ANM) जिसे आमतौर पर ANM के रूप में जाना जाता है, भारत में ग्रामीण स्तर की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसे समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच पहले संपर्क व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।

जननी सुरक्षा योजना (JSY): जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana- JSY) माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिये भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission-NHM) द्वारा चलाया जा रहा एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप (Safe Motherhood Intervention) है।

इसे 12 अप्रैल, 2005 को लॉन्च किया गया था और इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेष फोकस के साथ लागू किया जा रहा है।

JSY एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और प्रसव एवं प्रसव उपरांत देखभाल हेतु नकद सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): PMMVY गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिये एक योजना है।

इस योजना ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आँकड़ा पार कर लिया है।

यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer- DBT) योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद राशि प्रदान की जाती है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और आंशिक रूप से मज़दूरी के नुकसान की भरपाई की जा सके।

आगे की राह

बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण: महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिये बहु-क्षेत्रीय स्तर जैसे- बाल विवाह के उन्मूलन, गर्भ निरोधकों तक पहुँच और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये समान व्यवहार किया जाना चाहिये।

निस्संदेह मातृ स्वास्थ्य देखभाल महत्त्वपूर्ण है, अतः महिलाओं के पूरे जीवन काल में उनके स्वास्थ्य देखभाल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, नियमित जाँच और निवारक देखभाल ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता: अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिये स्वयं महिलाएँ अपनी तरफ से अनिच्छुक होती हैं।

यदि महिलाएँ अपने घरों के पास उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करें तो वे अपनी कई भूमिकाओं के कारण अपने लिये समय निकाल सकती हैं।

संयुक्त प्रयासः सशक्तीकरण हेतु महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिये और उन सुविधाओं से अवगत होना चाहिये जो सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही हैं।

गर्भवती महिलाओं के लिये नियमित जाँच अनिवार्य है और इसके माध्यम से उनके एनीमिया का ध्यान रखा जाना चाहिये तथा सुरक्षित परिस्थितियों में प्रसव सुनिश्चित करना चाहिये।

साथ ही समाज में पुरुषों की मानसिकता को बदलना होगा और उन्हें शिक्षित भी होना चाहिये।

महिलाओं के लिये और आखिरकार सभी के लिये अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

एक स्वस्थ समाज का निर्माण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती रहेगी क्योंकि वे एक स्वस्थ समाज की आधारशिला हैं।

महिलाओं का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित कराना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। भारत और इसकी अर्थव्यवस्था को एक स्वस्थ महिला कार्यबल की आवश्यकता है क्योंकि महिलाओं की श्रम शक्ति में 10 प्रतिशत की वृद्धि से वर्ष 2025 तक भारत की GDP में लगभग 700 बिलियन डॉलर की वृद्धि की जा सकती है।

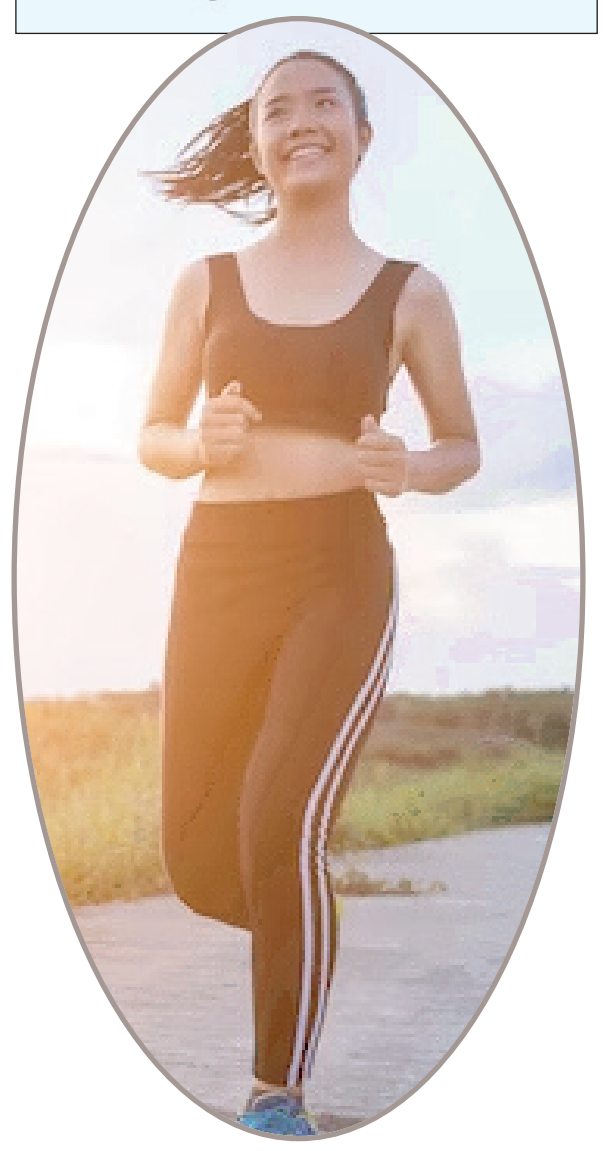

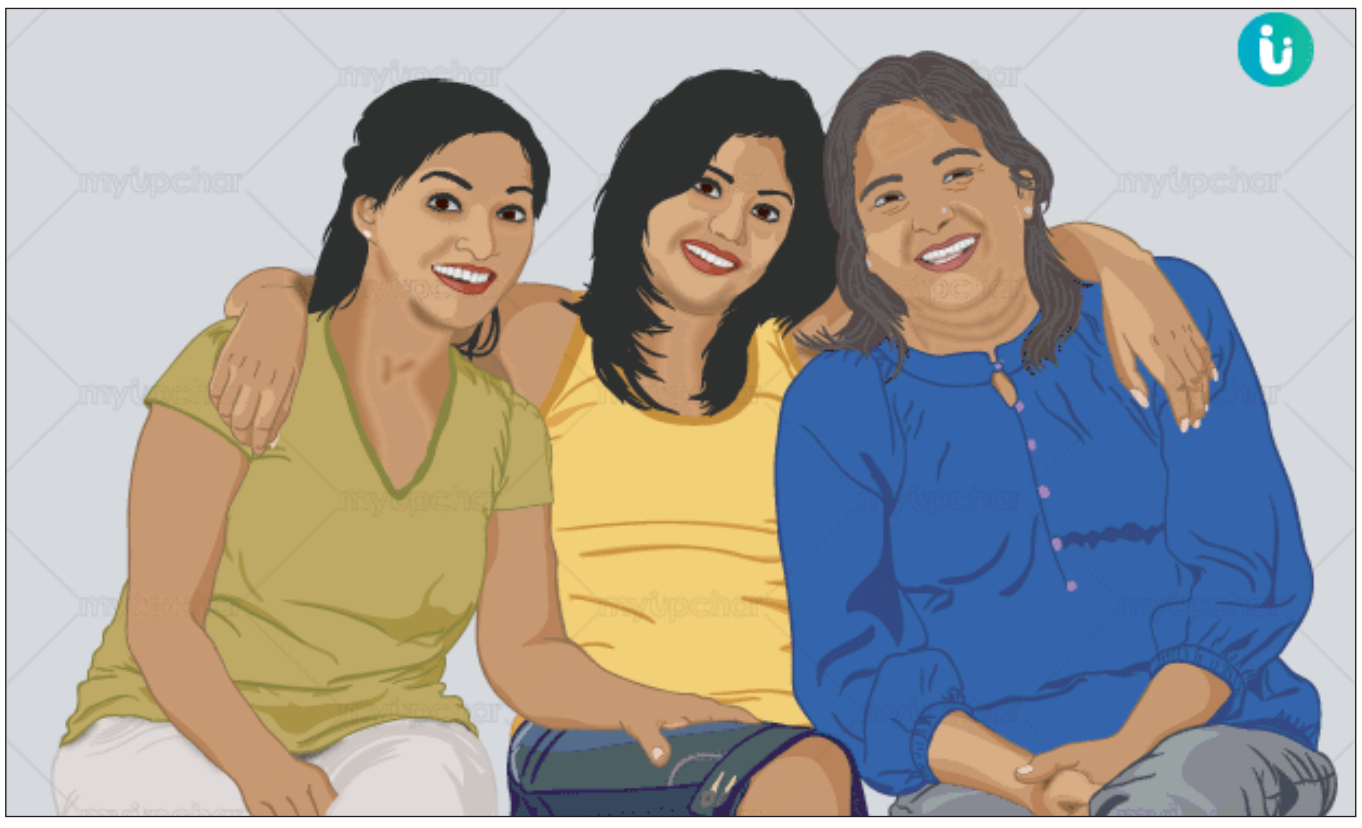

कैल्शियम की कमी से कम उम्र में ही घेर लेगी हड्डियों की बीमारी, कमी दूर करने के लिए महिलाएं जरूर खाएं ये 5 फूड

बढ़ती उम्र में हड्डियों से संबंधित कई समस्याएं घेरने लगती हैं. अक्सर महिलाएं अपने खानपान का ध्यान नहीं रखती हैं, जिससे उन्हें 30-40 की उम्र में ही बोन संबंधित प्रॉब्लम होने लगती हैं. ये परेशानी और अधिक ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि आप अभी से ही कैल्शियम से भरपूर फूड्स का सेवन शुरू कर दें. यहां 5 कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में बता रहे हैं, इन्हें आप जरूर खाएं.

उम्र बढ़ने के साथ शरीर के अंग धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं. हड्डियों के साथ भी ऐसा ही है. यदि आप कम उम्र हेल्दी और पौष्टिक से भरपूर फूड्स का सेवन नहीं करेंगी तो आगे चलकर कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं. सबसे ज्यादा लोगों को हड्डियों की समस्या परेशान करने लगती है. खासकर महिलाएं 30 से 40 की उम्र में ही शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण परेशान रहती हैं. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उनकी डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स की कमी होती है. आप नहीं चाहती हैं कि बढ़ती उम्र में आपको गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों में दर्द, बोन फ्रैक्चर की समस्या हो तो आप यहां बताए गए कैल्शियम से भरपूर चीजों को डाइट में आज से ही शामिल करें.

कैल्शिमय की जरूरत शरीर को क्यों होती है ?

हेल्थ डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, कैल्शियम शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल है. ये एक ऐसा पोषक तत्व है, जो आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है. मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है. नर्व और हार्मोन फंक्शन को सपोर्ट करता है. कैल्शियम को शरीर स्वाभाविक रूप से प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए, हड्डियों को मजबूती देने और बेहतर हेल्थ के लिए डाइट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम से भरपूर फूड्स को शामिल करना महत्वपूर्ण है. आपके शरीर में 99% से अधिक कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है.

कितना हो एक दिन में कैल्शियम का इनटेक

अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (2016 तक) के अनुसार, 4 से लेकर उससे अधिक उम्र वालों के लिए कैल्शियम का अनुशंसित डेली वैल्यू 1,300 मिलीग्राम निर्धारित किया है. हालांकि, कैल्शियम की जरूरत व्यक्ति की उम्र, लिंग पर आधारित होती है. फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के अनुसार कैल्शियम के लिए अनुशंसित डायटरी अलाउएंसेज (RDAs) अलग-अलग हैं. 14 से 18 वर्ष के टींस को 1300 एमजी डेली कैल्शियम इनटेक जरूरी है. वहीं 19 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 1000 एमजी. 51 से 70 वर्ष के पुरुषों को 1 हजार एमजी तो इसी उम्र की महिलाओं को 1200 एमजी कैल्शियम का डेली इनटेक जरूरी है.

कैल्शियम की पूर्ति के लिए महिलाएं खाएं ये फूड्स

खसखस- महिलाओं को कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध, दही के अलावा, खसखस को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. खसखस आयरन, कैल्शियम, गुड फैट का बेहतरीन सोर्स है. हालांकि, इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन आप सीमित मात्रा में ही करें. कैल्शियम रिच खसखस के नियमित सेवन से आप अपनी हड्डियों को बीमारियों से बचा सकती हैं.

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स- अक्सर महिलाएं घर के कामों में लगी रहती हैं और अपने खानपान पर ध्यान कम देती हैं. कुछ महिलाएं तो डेली दूध, दही का सेवन भी नहीं करती हैं. कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध और इससे बनी चीजें आप डेली खाएं. तभी बढ़ती उम्र में बोन रिलेटेड समस्याओं से बची रहेंगी. डेयरी प्रोडक्ट्स अन्य फूड्स की तुलना में कैल्शियम में सबसे अधिक भरपूर होते हैं. इसके लिए आप चीज की भी सेवन कर सकती हैं.

चिया सीड्स- ये बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होते हैं. इसे आप दही, स्मूदी, दूध या फिर पानी में डालकर भी पी सकती हैं. कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स हैं चिया के बीज. प्रत्येक 100 ग्राम सर्विंग में लगभग 400 से लेकर 600 एमजी कैल्शियम की पूर्ति होगी.

हरी पत्तेदार सब्जियां- सब्जियां सेहत का खजाना होती हैं. खासकर, हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से आपको भरपूर पोषण मिलेगा. इनमें विटामिन ए, सी, ई, के, आयरन, फाइबर के साथ ही कैल्शियम भी होता है. आप पालक, केल का सेवन जरूर करें. पत्तेदार सब्जियों के सेवन से महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी भी नहीं होगी. पालक खाने से आपको कैल्शियम, आयरन के साथ ही विटामिन ए, सी भी मिलेगा. केल का सेवन आप सलाद या किसी भी ड्रिंक में ब्लेंड करके कर सकती हैं.

नट्स और सीड्स- कुछ नट्स में कैल्शियम काफी अधिक होता है. बादाम, तिल, अलसी के बीज खाएं. इनसे आपको कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन के, कई तरह के मिनरल्स, फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स की प्राप्ति होगी. एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स के कारण कोशिकाओं को होने वाली नुकसान से बचाते हैं. कैल्शियम के लिए आप बादाम का सेवन भी कर सकती हैं.

'शर्म की बात है कि दिल्ली के कई घरों में नल से पानी नहीं पहुंचता', LG सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि यहां के कई क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पर नल से पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा है। जबकि केंद्र सरकार ने देश के कोने-कोने तक पानी पहुंचाया है उस क्षेत्र तक में भी पानी पहुंचाया है जहां संभव नहीं था।

परिवहन विशेष न्यूज

पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने खुद को दिल्ली का अभिभावक बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि यहां के कई क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पर नल से पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा है। जबकि केंद्र सरकार ने देश के कोने-कोने तक पानी पहुंचाया है, उस क्षेत्र तक में भी पानी पहुंचाया है जहां संभव नहीं था। भले ही एलजी ने किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना दिल्ली सरकार की तरफ था। यहां तक कहा कि दिल्ली बहुत पिछड़ गई थी, उसे फिर से मुख्यधारा में लाया जा रहा है।

बृहस्पतिवार को एलजी ने शास्त्री पार्क में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के साथ मिलकर डीडीए के कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। यह उत्तर-पूर्वी जिले का पहला कन्वेंशन सेंटर है, जिसे छह करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यहां लोग सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम के साथ ही शादी समारोह कर सकेंगे। यहां रसोई के साथ ही एक रेस्तरां भी है। एलजी ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में यहां के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं बराबर होनी चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी

उद्देश्य को लेकर वह काम कर रहे हैं।

960 करोड़ रुपये डीडीए को सौंपा गया

गांवों के विकास के लिए दिल्ली सरकार के पास पड़े 960 करोड़ रुपये सरकार से वापस लेकर डीडीए को सौंप दिए हैं। उस रकम से दिल्ली के दो सौ गांव को संवारा जा रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गांव में गैस की पाइपलाइन भी होगी। उन्होंने पांच गांव में पाइपलाइन डालने की शुरुआत करवा दी है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि दिल्ली को फूलों की नगरी बनाया जाए। पहले एनडीएमसी क्षेत्र में ही फूल लगाए जाते थे, लेकिन अब दिल्ली में जगह-जगह फूल लगाए जा रहे हैं।

LG की बदौलत ही कन्वेंशन सेंटर बन पाया: मनोज तिवारी

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एलजी की बदौलत ही कन्वेंशन सेंटर बन पाया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की आबादी 50 लाख है। यहां ऐसा कोई सेंटर नहीं था, जहां पर लोग बड़े स्तर पर सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम कर सकें। उन्हें कार्यक्रम करने के लिए नई दिल्ली जाना पड़ता था। इस मौके पर विधायक अजय महावर, मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व महापौर व पार्षद सत्या शर्मा, जिलाध्यक्ष पूनम चौहान व मनोज त्यागी मौजूद रहे।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक समान लीज डीड के ड्राफ्ट को दी मंजूरी, 5311 आवंटियों को होगा लाभ

उपराज्यपाल ने एक समान लीज डीड के एक ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। फ्लैटों की लीज डीड के निष्पादन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस स्कीम की शुरुआत लगभग दो दशक पहले हुई थी। सक्सेना ने प्रशासनिक सचिव को निर्देश दिया है कि वे विभाग में ऐसे मामलों की व्यापक समीक्षा करें जिनमें अत्यधिक देरी हुई है और उस पर शीघ्रता से कार्रवाई करें।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना और नरेला में विभिन्न वर्कर्स हाउसिंग स्कीम के तहत मूल आवंटियों और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) के बीच फ्लैटों की लीज डीड के निष्पादन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस स्कीम की शुरुआत लगभग दो दशक पहले हुई थी।

उपराज्यपाल ने एक समान लीज डीड के एक ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। मगर इसके साथ उन्होंने डीएसआइआइडीसी को फटकार भी लगाई है। उन्होंने फाइल में लिखा कि यह देखना चौंकाने वाला है कि 2003-2004 में पहली हाउसिंग स्कीम की शुरुआत से लगभग दो दशक बीत जाने के बाद भी लीज डीड के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

बवाना में वर्ष 2003-2004 में राजीव गांधी आवास योजना (आरजीएचएस)-I और वर्ष 2006-2007 में नरेला और बवाना में आरजीएचएस-II की शुरुआत की गई थी।उन्होंने इस पर चिंता जताई कि श्रमिकों की आवास योजनाओं के संबंध में 2019 में उनके पूर्ववर्ती द्वारा लीज डीड के निष्पादन में देरी का कारण बताने के लिए स्पष्ट रूप से दिए निर्देशों के बावजूद डीएसआइआइडीसी ने लीज डीड को अंतिम रूप देने के मामले में अकारण ही लगभग 5 वर्षों की देरी की।

उन्होंने इस मामले में अब किसी भी तरह की देरी को बर्दाश्त न करने और लीज डीड के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया करे तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए।इससे 5311 आवंटियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि मामला विभिन्न योजनाओं के तहत फ्लैटों के आवंटन से संबंधित है।जिसमें आरजीएचएस -I में 2006-07 में 2820 व्यक्तिगत इंडस्ट्रियल वर्कर्स का आवंटन, आरजीएचएस-II के तहत 2014 और 2017 में 150 405 व्यक्तिगत औद्योगिक श्रमिक को आवंटन शामिल है।

इसके अलावा 2010 में प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से 384 फ्लैटों का संस्थागत आवंटन 2012 और 2015-18 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से 512 और 1040 फ्लैटों का संस्थागत आवंटन शामिल है।

नहीं पता था... सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाया, दिल्ली में रैट माइनर का घर गिराने पर DDA ने रखा पक्ष

परिवहन विशेष न्यूज

पूर्वी दिल्ली। खजूरी खास क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी में ध्वस्त किए गए रैट माइनर के मकान को लेकर डीडीए ने अपना पक्ष रखा है। डीडीए ने बयान जारी कर कहा है कि अतिक्रमण हटाने की सामान्य कार्रवाई के तहत ध्वस्तीकरण किया गया है। रैट माइनर वकील हसन ने जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाया हुआ था। कार्रवाई से पहले उनको मकान खाली करने का प्रर्याप्त समय दिया गया था।

डीडीए ने रखा ये प्रस्ताव

साथ ही यह भी कहा कि कार्रवाई से पहले और उसके दौरान डीडीए के किसी अधिकारी को उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे कामगारों को बचाने में वकील के हाल के योगदान के बारे में जानकारी नहीं थी। देर शाम उनके योगदान के बारे में मालूम होने पर डीडीए की ओर से उनके आश्रय की वैकल्पिक व्यवस्था की थी, लेकिन वकील ने

उसके लिए मना कर दिया।

वह यहीं पर या दूसरी जगह पक्का देने की मांग कर रहे थे। देर रात कई अधिकारी वहां पर गए भी थे। डीडीए की ओर से बताया गया कि वर्ष 2016 में यहां पर तीन भूखंडों को अतिक्रमण हटाकर खाली कराया गया था। वर्ष 2017 में निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि उनमें से दो भूखंडों पर वकील व एक अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। इस अतिक्रमण के संबंध में तत्काल पुलिस को शिकायत की गई थी और जून 2018 में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी।

लोगों ने दी आत्मदाह की धमकी

हालांकि टीम जब अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी तो उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अतिक्रमणकारियों के रूप में पहचाने जाने वाले परिवार ने इसका विरोध किया था। उस समय अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। फिर सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 में कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी। उस दौरान फिर परिवार की महिलाओं ने खुद को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और परिसर के भीतर आत्मदाह की धमकी दी थी। डीडीए ने कहा कि वकील को जमीन के स्टेट्स के संबंध में सब पता था।

आरवीएसएफ उद्योग के दिग्गजों ने मिलकर एमओआरटीएच के निदेशक (परिवहन) श्री परेश गोयल के साथ बैठक की

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। एमआरएआई ने श्री जगदीश प्रसाद, श्री विक्रम जीत बख्शी, श्री लॉरेंस पिंटो, श्री अनिरुद्ध केडिया सहित आरवीएसएफ उद्योग के दिग्गजों को साथ लेकर एमओआरटीएच के निदेशक (परिवहन) श्री परेश गोयल के साथ बैठक की।

यह बैठक मुख्य रूप से 17 फरवरी, 2024 को आरवीएसएफ बिरादरी की आपस मे हुई बातचीत/चर्चा किए गए मुद्दों की विस्तृत सूची के साथ एक औपचारिक पत्र (पहले से ही सम्मानित सदस्यों के साथ साझा किया गया) के रूप में एम.ओ.आर.टी.एच. को भेजे गए प्रतिनिधित्व के क्रम में की गई थी। इस चर्चा में अन्य बिंदुओं के अलावा "ऑरेंज श्रेणी पात्रता", "जियो-फेंसिंग के साथ जियो टैगिंग" जैसे मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई।

सभी आरवीएसएफ के कहे अनुसार यह बैठक और चर्चा सार्थक रही और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसकी एमओएम को उपस्थित सदस्यों के साथ गहन परामर्श और समेकन के बाद शीघ्र ही साझा किया जाएगा।

केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा ठग सुकेश चंद्रशेखर, दिल्ली CM को लिखी चिट्ठी में

परिवहन विशेष न्यूज

ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। इस चिट्ठी के माध्यम से उसने दावा किया कि उसे कर्नाटक या तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट ऑफर किया गया है। उसने लेटर में एलान किया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के आगामी विधानसभा का निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेगा।

नई दिल्ली। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के माध्यम से सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाए हैं और एक मोबाइल नंबर के बारे में भी पूछा। इसके साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने एलान किया है कि वह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।

लोकसभा चुनाव के टिकट का ऑफर

अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में सुकेश ने कहा कि पिछले 2 महीने से सब कुछ खामोश था, मैं भी सोच रहा था कि सब कैसे चुप हो गए कि मुझे धमकियां और ऑफर नहीं भेज रहे हैं। हालांकि, पिछले 3 दिनों से एक बार फिर शुरू हो गया है। सुकेश ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि जेल प्रशासन के माध्यम से दबाव की रणनीति और तमिलनाडु या कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के टिकट ऑफर किए हैं।

केजरीवाल को लेकर सुकेश ने कही ये बात

उसने केजरीवाल को संबोधित करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन और आपके खिलाफ दिए बयान से मुकरने के लिए टिकट देने का ऑफर किया गया है। साथ ही सुकेश ने लेटर में केजरीवाल से कहा कि अब समय आ गया है, मेरे भाई, अपनी घड़ी और कैलेंडर को देखना शुरू करो, उलटी गिनती शुरू हो गई है। हमारे देश में हर कोई आपके भ्रष्टाचार की सच्चाई जानता है, और अब तो कोर्ट भी जानती है, इसीलिए आपकी सारी ठग कॉन टीम अभी भी जेल में है।

सुकेश चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ने का कहा

सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से आपके सामने दो बातों की घोषणा की हैं, पहला- मैं आपके सभी ऑफर को रिजेक्ट करता हूं और मुझे आपकी धमकियों की भी परवाह नहीं है। दूसरा- मैं दिल्ली में आपके खिलाफ आपके के ही निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय में चुनाव चुनाव लड़ूंगा।

दिल्ली के पार्क में नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या, झगड़े के बाद दिया घटना को अंजाम; पकड़े गए तीनों आरोपी किशोर

पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके के एक पार्क में तीन लड़कों ने कथित तौर पर 15 वर्षीय एक नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे इंद्रपुरी थाने में हरित पार्क में एक लड़के को चाकू मारने की सूचना मिली। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित र दिया।

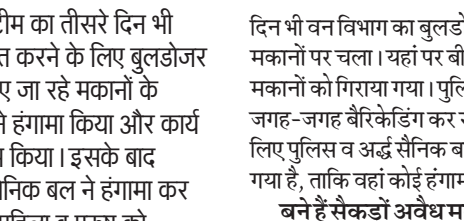

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके के एक पार्क में तीन लड़कों ने कथित तौर पर 15 वर्षीय एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे इंद्रपुरी थाने में हरित पार्क में एक लड़के को चाकू मारने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इंद्रपुरी निवासी इस किशोर को घायल पाया। उसे तत्काल नारायणा के कपूर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

तीनों का पीड़ित के साथ हुआ था झगड़ा

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विचित्र वीर ने कहा कि पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि तीन लड़कों (सभी किशोर) का पीड़ित और उसके दोस्त के साथ पार्क में झगड़ा हुआ था। उन्होंने पीड़ित पर चाकुओं से हमला किया। पीड़ित की छाती और पेट पर चोटें आई हैं। तीनों किशोर को हिरासत में ले लिया गया है और अपराध में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए हैं।

दिल्ली के लोगों ने ली साफ हवा में सांस! 7 साल में इस बार फरवरी में सबसे कम रहा प्रदूषण

परिवहन विशेष न्यूज

इस बार फरवरी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) और पीएम-2.5 का औसत स्तर वर्ष 2018 से अब तक सात वर्षों में सबसे कम रहा। इस बार फरवरी में औसत एक्यूआइ 218 और पीएम-2.5 का औसत स्तर 104 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। इस बार फरवरी में पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक वर्षा हुई है। इसे प्रदूषण कम होने का एक कारण माना जा रहा है।

नई दिल्ली। राजधानी में लगातार पिछले आठ दिनों से हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। इसलिए प्रदूषण से अभी राहत है। इस बीच शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि इस बार फरवरी माह में प्रदूषण का स्तर पिछले सात वर्षों में सबसे कम रहा है।

10 साल में सबसे ज्यादा बारिश

इससे लोगों ने प्रदूषण से राहत की सांस ली। आयोग ने इस बार प्रदूषण कम होने का कोई कारण तो नहीं बताया है, लेकिन इस बार फरवरी में पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक वर्षा हुई है। इसे प्रदूषण कम होने का एक कारण माना जा रहा है।

आयोग द्वारा जारी आंकड़े में कहा गया है कि इस बार फरवरी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) और पीएम-2.5 का औसत स्तर वर्ष 2018 से अब तक सात वर्षों में सबसे कम रहा। इस बार फरवरी में औसत एक्यूआइ 218 और पीएम-2.5 का औसत स्तर 104 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा।

15 दिन मध्यम श्रेणी की रही हवा की गुणवत्ता

मध्यम वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या इस बार अधिक रही और खराब से गंभीर श्रेणी की वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या कम रही, लेकिन इस बार फरवरी में एक दिन भी एक्यूआइ 100 से नीचे नहीं रहा। इसलिए एक भी दिन भी बिल्कुल स्वच्छ हवा तो नहीं मिली, लेकिन इस बार फरवरी में 15 दिन हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। इस दौरान एक्यूआइ 100 से 200 के बीच रही।

दस दिन हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में और चार दिन बहुत खराब श्रेणी में रही। इस बार फरवरी में 32.5 मिलीमीटर वर्षा हुई जो सामान्य से 53 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले वर्ष 2014 में फरवरी में 48.8 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। माह के आखिरी दिन भी दिल्ली में एक्यूआइ 147 रहा जो मध्यम श्रेणी में है। एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में भी एयर इंडेक्स 200 से कम होने से हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही।

दिल्ली में लगातार तीसरे दिन अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, विरोध करने वालों को हिरासत में लिया

वन विभाग की टीम का तीसरे दिन भी मकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चला। ध्वस्त किए जा रहे मकानों के विरोध में लोगों ने हंगामा किया और कार्य रोकने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस व अर्द्ध सैनिक बल ने हंगामा कर रहे करीब सात महिला व पुरुष को हिरासत में लिया और उन्हें वहां से दूर ले गए।

दिल्ली। संगम विहार इलाके में तीसरे दिन भी वन विभाग का बुलडोजर अवैध मकानों पर चला। यहां पर बीस से अधिक मकानों को गिराया गया। पुलिस ने इलाके में जगह-जगह बैरिकेडिंग कर रखी है। सुरक्षा के लिए पुलिस व अर्द्ध सैनिक बल तैनात किया गया है, ताकि वहां कोई हंगामा न कर सकें।

बने हैं सैकड़ों अवैध मकान

संगम विहार इलाके में वन विभाग की जमीन पर सैकड़ों की संख्या पर अवैध रूप से मकान बने हुए है। इन मकानों को ध्वस्त करने के लिए वन विभाग की टीम का तीसरे दिन भी मकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चला। ध्वस्त किए जा रहे मकानों के विरोध में लोगों ने हंगामा किया और कार्य रोकने का प्रयास किया।

इसके बाद पुलिस व अर्द्ध सैनिक बल ने हंगामा कर रहे करीब सात महिला व पुरुष को हिरासत में लिया और उन्हें वहां से दूर ले गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मकान टूटने से संगम विहार में अफरा-तफरी का माहौल रहा। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए सभी अवैध मकानों को तोड़ा जाएगा।

पुलिस व अर्द्ध सैनिक बल रहा तैनात

संगम विहार इलाके में वन विभाग की जमीन पर बने मकानों के आसपास पुलिस व अर्द्ध सैनिक बल तैनात रहा। इलाके को छावनी में तब्दील कर सभी गलियों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। वहां किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। यदि कोई जाने का प्रयास करता तो उसको वहां से भगा दिया जाता था।

नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक बसेगी मिनी मुंबई...

यमुना अथॉरिटी 100 एकड़ में बनाएगी फिनटेक सिटी

परिवहन विशेष न्यूज

मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी की पहचान मिली हुई है। इसी की तर्ज पर फिनटेक सिटी को वाणिज्यक एवं वित्तीय संस्थानों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 13 में फिनटेक सिटी के विकास का निर्माण लिया है। इसे सौ एकड़ में विकसित किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए कंपनियों ने प्रस्ताव मांगे थे।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मिनी मुंबई (फिनटेक सिटी) बसाई जाएगी। इसका खाका कुशमन एंड वेकफील्ड इंडिया प्रा. लि. कंपनी तैयार करेगी। यमुना प्राधिकरण में बुधवार को खोली गई वित्तीय निविदा में पांच कंपनियों में से कुशमन एंड वेकफील्ड इंडिया प्रा. लि. का चयन फिनटेक सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया है।

कंपनी 45 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। फिनटेक सिटी यीडा समेत गौतमबुद्ध नगर में आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनेगा। इसमें हजारों लोगों को रोजगार के अवसर के साथ वित्तीय संस्थानों से संबंधित कार्यों को एक ही क्लस्टर में कराने की सुविधा मिल जाएगी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। वाणिज्य के साथ औद्योगिक ढांचे का यीडा क्षेत्र में विकास हो रहा है।

सेक्टर 13 में बनेगी फिनटेक सिटी

इसलिए यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 13 में फिनटेक सिटी के विकास का निर्माण लिया है। इसे सौ एकड़ में विकसित किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए कंपनियों ने प्रस्ताव मांगे थे। वैश्विक निविदा में सीबीआरई साउथ एशिया प्रा. लि., कुशमन एंड वेकफील्ड इंडिया प्रा. लि., जोन्स लेंग ला सेले प्रापर्टी कंसल्टेंट इंडिया प्रा. लि., ट्रेक्टेबल इंजीनियर्स प्रा. लि. और वायन्ट्स सल्यूशन प्रा. लि. तकनीकी निविदा में सफल रही थीं। वित्तीय निविदा में कुशमन एंड वेकफील्ड इंडिया प्रा. लि. का चयन किया गया है। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि 45 दिन में कंपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी।

विकास के मॉडल पर देगी सुझाव

चयनित कंपनी फिनटेक सिटी के विकास पर सुझाव देगी कि इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाए या फिर प्राधिकरण सीधे वित्तीय संस्थानों को सीधे भूखंड का आवंटन करे। इसके साथ ही

फिनटेक सिटी में कौन-कौन सी सुविधाएं विकसित होनी चाहिए, इनके लिए किनता क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा। फिनटेक सिटी को विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना फायदेमंद होगा की नहीं। केंद्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए फिनटेक सिटी की केंद्र सरकार से अधिसूचना जारी करना जरूरी है या नहीं आदि पर भी कंपनी अपने सुझाव देगी।

मुंबई की तरह बनेगी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र

मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी की पहचान मिली हुई है। इसी की तर्ज पर फिनटेक सिटी को वाणिज्यक एवं वित्तीय संस्थानों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पचास प्रतिशत में कामर्शियल, शेष में आवासीय, कोर फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ग्लोबल सेंटर आफ एक्सीलेंस, एलाइड कामर्शियल सर्विस, फाइनेंशियल प्रोसेसिंग, बैंक, वित्तीय, शेयर एक्सचेंज, बीमा कंपनियों के कार्यालय समेत वित्तीय क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां होंगी। इसका 250 एकड़ तक विस्तार किया जाएगा।

देश में बढ़ रहा फिनटेक मार्केट

2022 में भारत में 46 प्रतिशत लेनदेन रियल टाइम में हुआ। भारत में फिनटेक मार्केट 15000 करोड़ रुपये का है। 2030 में यह बढ़कर 23700 करोड़ रुपये का हो जाएगा।

नकाबपोश ने महिला पर डाला तेजाब, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती; पति की तलाश में पुलिस

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम के पालम विहार थाना क्षेत्र में अंसल प्लाजा के पास एक नकाबपोश शख्स ने महिला पर तेजाब फेंक दिया। इससे महिला के हाथ पैर और कमर बुरी तरह झुलस गए। आसपास के लोग पहले उसे नागरिक अस्पताल ले ले गए। महिला ने अपने पति पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया है।पुलिस मामले में केस दर्ज कर आरोपित पति की तलाश में जुट गई है।

गुरुग्राम। पालम विहार थाना क्षेत्र में अंसल प्लाजा के पास एक नकाबपोश व्यक्ति ने महिला पर तेजाब फेंक दिया। इससे महिला के हाथ, पैर और कमर बुरी तरह झुलस गए। आसपास के लोग पहले उसे नागरिक अस्पताल ले ले गए। यहां से उसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। महिला ने अपने पति पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया है।पुलिस मामले में केस दर्ज कर आरोपित पति की तलाश में जुट गई है।

पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय नरगिस परवीन चार महीने से गांव चौमा में अपने चार बच्चों के साथ रहती हैं। उनका अपने पति से काफी समय से विवाद चला आ रहा है। इस कारण वह घरेलू सहायिका का काम कर अपना जीवन-यापन करती हैं। बताया जाता है कि शाम साढ़े छह नरगिस एक घर से काम खत्म कर वापस चौमा जा रही थीं।

लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया

अंसल प्लाजा के पास अचानक नकाबपोश व्यक्ति ने उन पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। महिला कुछ समझ पाती कि उसके कपड़े जलने लगे और एसिड के कारण उसके शरीर में जलन होने लगी। शोर मचाने पर लोग एकत्र हुए और उसे अस्पताल ले जाया गया।

पति पर ही तेजाब फेंकने का शक

पालम विहार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजयवीर सिंह ने बताया कि महिला ने अपने पति पर ही तेजाब फेंकने का शक जताते हुए शिकायत दी है। महिला का अपने पति से विवाद चला आ रहा है। महिला पति की दूसरी पत्नी है। आरोपित पति की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है।

प्राधिकरण ने सर्वे करा 550 उन स्थानों को चिह्नित किया है, जो अतिसंवेदनशील है। सेफ सिटी परियोजना पर प्राधिकरण ने दो सौ करोड़ रुपये खर्च करने का बजट निर्धारित किया है।

बेंगलुरु की तर्ज पर नोएडा में सेफ सिटी बनाने की योजना तैयार, सुरक्षा में लगेंगी 2500 'तीसरी आंख

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा प्राधिकरण ने बेंगलुरु की तर्ज पर सेफ सिटी बनाने की योजना तैयार की है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखने के लिए 2500 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है। जिन 550 स्थानों पर कैमरे लगाए जाने है उसकी सूची पुलिस प्रशासन ने नोएडा प्राधिकरण को सौंप दी है। सूची में भीड़ भाड़ वाले बाजार के अलावा स्कूल धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे।

नोएडा। शहर व निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने बेंगलुरु की तर्ज पर सेफ सिटी बनाने की योजना तैयार की है, जिसको धरातल पर उतरने की दिशा में अब कदम बढ़ा दिया है। ऐसे में शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखने के लिए 2500 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है।

यह कैमरे कहां कहां पर लगाकर कंट्रोल रूम के जरिये आसानी से मानिटरिंग की जा सके। इसके लिए प्राधिकरण ने सर्वे करा 550 उन स्थानों को चिह्नित किया है, जो अतिसंवेदनशील है। सेफ सिटी परियोजना पर प्राधिकरण ने दो सौ करोड़ रुपये खर्च करने का बजट निर्धारित किया है। मार्च में इस परियोजना के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा।

550 स्थानों पर लगाए जाने हैं कैमरे

बता दें कि जिन 550 स्थानों पर कैमरे लगाए जाने है, उसकी सूची पुलिस प्रशासन ने नोएडा प्राधिकरण को सौंप दी है। सूची में भीड़ भाड़ वाले बाजार के अलावा स्कूल, धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे आइएसटीएमएस की बजाए सेफ सिटी के तहत लगाए जाएंगे।

इनका वाहनों के चालान से कोई संबंध नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा के तहत वाहनों की नंबर प्लेट व उसमें बैठे लोग भी साफ तौर पर कैमरों में नजर आएंगे। जिन जगह कैमरे लगाए जाएंगे उनमें अधिकतर हिस्सा शहरी क्षेत्र ही है।

पुलिस मुख्यालय से जुड़ेगा कंट्रोल रूम

सेफ सिटी के कंट्रोल रूम सीधे पुलिस मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। जिससे कोई भी जानकारी या सूचना मिलने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन, चौकी और पीआरवी और

डायल-112 को जानकारी दी जा सकेगी। योजना के तहत फेस डिटेक्शन कैमरे लगाए जाएंगे।

बदमाशों का डाटा पुलिस के पास पहले से रहेगा। ऐसे में कोई भी बदमाश यदि इन कैमरों की जद में आता है तो उसकी लाइव लोकेशन और पूरा डाटा कंट्रोल रूम में दिखाई देगा। जिससे उसे आसानी से पकड़ा जा सकेगा। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद इसकी पूरी ट्रैनिंग पुलिस को देगी।

सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

पैन टिल्ट जूम कैमरा किसी भी समय चारों तरफ घुमाया जा सकता है। इसके साथ ही करीब 1700 मीटर तक इसकी रिकार्डिंग जूम कर साफ देखी जा सकेगी। बुलेट कैमरा 250 से ज्यादा की स्पीड में गुजरे वाहन की फुटेज बनाने में सक्षम होंगे। आटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर व सामान्य सीसीटीवी पहले से आइटीएमएस में लगे हुए हैं।

सेफ सिटी परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गया है, मार्च में इस परियोजना के तहत काम शुरू कर दिया जाएगा। -डॉ. लोकेश एम, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण।

प्रजापति समाज की यात्रा पुलिस ने कादराबाद में रोकी, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा; तोड़ी बैरिकेडिंग

हरिद्वार से दिल्ली जा रही प्रजापति समाज के लोगों की यात्रा को पुलिस ने मोदीनगर के कादराबाद पर रोक लिया। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने सड़क को ब्लॉक कर दिया। गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सड़क जाम कर दी गई। लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की गई। सभी आगे जाने की जिद पर अड़े हुए हैं।

गाजियाबाद। हरिद्वार से दिल्ली जा रही प्रजापति समाज के लोगों की यात्रा को पुलिस ने मोदीनगर में कादराबाद पर रोक लिया। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने सड़क को ब्लॉक कर दिया है। गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सड़क जाम कर दी गई है। प्रजापति समाज के लोग आगे जाने की जिद पर अड़े हैं। पुलिस उन्हें समझाने में जुटी है। वहीं आक्रोशित लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। लोगों ने पुलिस से धक्का-मुक्की की। लोगों ने आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर पदयात्रा शुरू की है। प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने की उनकी तैयारी है। तीन चार थानों का बल मौके पर बुलाया गया है।

घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, फ्लैट खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक

अमिताभ कांत की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने के बाद नोएडा में पहली बार फ्लैट खरीदारों को उनका मालिकाना हक मिलने जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि अभी 29 .86 करोड़ रुपये प्राधिकरण में जमा हुए है। इसमें करीब 600 फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिलेगा। एक मार्च को हम 100 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री करेंगे।

नोएडा। शासन की मंजूरी के बाद नोएडा प्राधिकरण में अमिताभ कांत रिपोर्ट की सिफारिश को लागू किया गया। रिपोर्ट लागू करने के बाद पहली बार एक मार्च को शहर में 100 फ्लैट खरीदारों को उनका मालिकाना हक मिलने जा रहा है। इसके लिए एक्सप्रेस बिल्डर एंड प्रमोटर्स सेक्टर-77 में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। यहां प्राधिकरण, फ्लैट खरीदार, निबंधन विभाग अधिकारी मौजूद रहेंगे।

शिविर लगाकर होगी रजिस्ट्री

शिविर लगाकर फ्लैट की रजिस्ट्री की जाएगी। बता दें कि सिफारिश के तहत कुल 35 बिल्डरों ने नोएडा प्राधिकरण में सहमति दी है। सभी बिल्डर 2209 करोड़ रुपये प्राधिकरण में जमा कराएंगे। इससे 13 हजार 639 फ्लैट खरीदारों को उनको मालिकाना हक मिल जाएगा। सिफारिश के तहत अभी इसी बकाया का 25 प्रतिशत जमा किया जा रहा है। यह कुल बकाया के 552.51 करोड़ है। इसके जमा होने पर 3412 रजिस्ट्री हो जाएगी।

600 खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक

नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि अभी 29.86 करोड़ रुपये प्राधिकरण में जमा हुए है। इसमें करीब 600 फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिलेगा। एक मार्च को हम 100 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री करेंगे। इसके लिए शिविर लगाया जाएगा।

अधिकतम मतदान के जरिये ही देश की राजनीति को सुधारा जा सकता है

ललित गर्ग

अधिकतम वोटिंग का वास्तविक उद्देश्य है, जन-जन में लोकतंत्र के प्रति आस्था पैदा करना, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित करना, वोट देने के लिए प्रेरित करना। एक जनक्रांति के रूप 'भारतीय मतदाता संगठन' इस मुहिम के लिये सक्रिय हुआ है, यह शुभ संकेत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से तीन माह के लिए विराम लेते हुए लोकतंत्र के महाकुंभ चुनाव में पहली बार वोटर बने युवाओं से रिकार्ड संख्या में मतदान का आग्रह किया। अधिकतम संख्या में मतदान लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण होने के साथ लोकतंत्र के बलशाली होने का आधार हैं और जनता की सक्रिय भागीदारी का सूचक है। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है, इनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। इसीलिये मोदी ने मतदान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान करके एक जागरूक, सक्षम एवं जुझारु राजनेता का परिचय दिया है। अधिकतम मतदान भारतीय लोकतंत्र को अधिक स्वस्थ, सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की एक सार्थक मुहिम है। सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति वैसा ही उत्साह दिखाना चाहिए जैसा कुछ समय से महिलाएं दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से यह भी अपील की कि वे राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनें और राजनीतिक-चर्चाओं को लेकर जागरूक भी रहें। विशेषतः विभिन्न राजनीतिक दलों की लोकलुभावन घोषणाओं एवं चुनावी घोषणा पत्रों पर युवाओं को गहराई से जानकारी हासिल करना चाहिए कि इन घोषणाओं का आधार क्या है, इनके लिये धन कहां से आयेगा? चुनावी तैयारियों का जायजा लेने चेन्नई गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसी बात को उठाते हुए कहा है कि यदि राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्रों में लोकलुभावन वादे करने का अधिकार है तो मतदाताओं को यह जानने का हक भी है कि क्या वे वादे व्यावहारिक हैं और उन्हें लागू करने के लिए धन का प्रबंध कहां से किया जाएगा।

अगले माह लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा और उसके चलते आचार संहिता लागू हो जायेगी। अधिकतम मतदान लोकतंत्र में जन-भागीदारी का अवसर मात्र ही नहीं हैं, बल्कि देश की दशा-दिशा तय करने में आम आदमी के योगदान का भी परिचायक है। अधिकतम मतदान के लिए माहौल बनाने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में मतदान प्रतिशत अपेक्षा से कहीं कम होता है। विडंबना यह है कि आमतौर पर कम प्रतिशत महानगरों में अधिक देखने को मिलता है। इसका कोई मतलब नहीं कि सरकारों अथवा राजनीतिक दलों के तौर-तरीकों की आलोचना तो बढ़-चढ़कर की जाए, लेकिन मतदान करने में उदासीनता दिखाई जाए। आमतौर पर मतदान न करने के पीछे यह तर्क अधिक सुनने को मिलता है कि मेरे अकेले के मत से क्या फर्क पड़ता है? एक तो यह तर्क सही नहीं, क्योंकि कई बार दो-चार मतों से भी हार-जीत होती है और दूसरे, अगर सभी यह सोचने लगें तो फिर लोकतंत्र कैसे सबल एवं सक्षम होगा? इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी का अधिकतम मतदान को प्रोत्साहन देने का उपक्रम एवं आह्वान एक क्रांतिकारी शुरुआत कही जा सकती है। इसका स्वागत हम इस सोच और संकल्प के साथ करें कि हमें अपने मतदान से आगामी आम चुनाव में भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण एवं राजनीतिक विसंगतियों पर नियंत्रण करना है।

अधिकतम मतदान के संकल्प से हमें मतदान का औसत प्रतिशत 55 से 90-95 प्रतिशत तक ले जाना चाहिए, ताकि इस लक्ष्य को हासिल करके हम भारतीय राजनीति की तस्वीर को नया रुख दे सके। मतदान करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और कर्तव्य भी है, लेकिन विडम्बना है हमारे देश की कि आजादी के 77 वर्षों बाद भी नागरिक लोकतंत्र की मजबूती के लिये निष्क्रिय है। ऐसा लगता है जमीन आजाद हुई है, जमीर तो आज भी कहीं, किसी के पास गिरवी रखा हुआ है। अधिकतम मतदान की दृष्टि से नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक

अलख जगाई थी। अनिवार्य वोट के लिये कानून लागू करना ही होगा और इस पहल के लिये सभी दलों को बाध्य होना ही होगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में यह नई जान फूंक सकती है। अब तक दुनिया के 32 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है लेकिन यही व्यवस्था अगर भारत में लागू हो गई तो उसकी बात ही कुछ और होगी और वह दुनिया के लिये अनुकरणीय साबित होगी। यदि ऐसा हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पुराने और सशक्त लोकतंत्रों को भी भारत का अनुसरण करना पड़ सकता है, हालांकि भारत और उनकी परिस्थितियां एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। भारत में अमीर लोग वोट नहीं डालते और इन देशों में गरीब लोग वोट नहीं डालते।

भारत इस तथ्य पर गर्व कर सकता है कि जितने मतदाता भारत में हैं, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं और लगभग हर साल भारत में कोई न कोई ऐसा चुनाव अवश्य होता है, जिसमें करोड़ों लोग वोट डालते हैं लेकिन अगर हम थोड़ा गहरे उतरें तो हमें बड़ी निराशा भी हो सकती है, क्या हमें यह तथ्य पता है कि पिछले 77 साल में हमारे यहां एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी, जिसे कभी 50 प्रतिशत वोट मिले हों। कुल वोटों के 50 प्रतिशत नहीं, जितने वोट पड़े, उनका भी 50 प्रतिशत नहीं। गणित की दृष्टि से देखें तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 20-25 करोड़ लोगों के समर्थन वाली सरकार क्या वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार है? क्या वह वैध सरकार है? क्या वह बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है? आज तक हम ऐसी सरकारों के आधीन ही रहे हैं, इसी के कारण लोकतंत्र में विषमताएं एवं विसंगतियों का बाहुल्य रहा है, लोकतंत्र के नाम पर यह छलावा हमारे साथ होता रहा है। इसके जिम्मेदार जितने राजनीति दल है उतने ही हम भी है। यह एक त्रासदी ही है कि हम वोट महोत्सव को कमतर आंकते रहे हैं। जबकि आज यह बताने और जताने की जरूरत है कि इस भारत के मालिक आप और हम सभी हैं और हम जागे हुए हैं। हम सो नहीं रहे हैं। हम धोखा नहीं खा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील करते हुए यह सही कहा कि अधिक से अधिक मतदान का मतलब एक मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत लोकतंत्र से ही विकसित भारत बनेगा, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था एवं तकनीक विकसित करने का भी समय आ गया है जिससे अपने गांव-शहर से दूर रहने वाले वहां जाए बगैर मतदान कर सकें। ध्यान रहे कि ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। रोजी-रोटी के लिए अपने गांव-शहर से दूर जाकर जीवनयापन करने वाले सब लोगों के लिए यह संभव नहीं कि वे मतदान करने अपने घर-गांव लौट सकें। यदि सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ-साथ चुनाव ड्यूटी में शामिल लोगों के लिए वोट देने की व्यवस्था हो सकती है तो अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकती? इस बार ऐसी किसी व्यवस्था के निर्माण के लिए निर्वाचन आयोग के साथ सरकार का भी सक्रिय होना समय की मांग है। इसी से हम अधिकतम मतदान के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे।

अधिकतम वोटिंग का वास्तविक उद्देश्य है, जन-जन में लोकतंत्र के प्रति आस्था पैदा करना, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित करना, वोट देने के लिए प्रेरित करना। एक जनक्रांति के रूप 'भारतीय मतदाता संगठन' इस मुहिम के लिये सक्रिय हुआ है, यह शुभ संकेत है। इस तरह के जन-आन्दोलन के साथ-साथ भारतीय संविधान में अनिवार्य मतदान के लिये कानूनी प्रावधान बनाये जाने की तीव्र अपेक्षा है। बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, ग्रीस, बोलिनिया और इटली जैसे देशों की भांति हमारे कानून में भी मतदान न करने वालों के लिये मामूली जुर्माना निश्चित होना चाहिए। यदि भारत में मतदान अनिवार्य हो जाए तो चुनावी भ्रष्टाचार बहुत घट जाएगा। यह भी देखा गया है कि चुनावों में येन-केन-प्रकारेण जीतने के लिये ये ही राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदान को बाधित भी करते हैं और उससे भी मतदान का प्रतिशत घटता है। अधिकतम मतदान से इस तरह के भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वोट-बैंक की राजनीति थोड़ी पतली पड़ेगी। जिस दिन भारत के 90 प्रतिशत से अधिक नागरिक वोट डालने लगेंगे, राजनीतिक जागरूकता इतनी बढ़ जाएगी कि राजनीति को सेवा की बजाय सुखों की सेज मानने वाले किसी तरह का दुस्साहस नहीं कर पायेंगे। राजनीति को सेवा या मिशन के रूप में लेने वाले ही जन-स्वीकार्य होंगे।

ऐलन मस्क की टेस्ला ला रही है सुपरफास्ट रोडस्टर ईवी, एक सेकेंड में पकड़ेगी 0-100 KMPH की रफ्तार

परिवहन विशेष न्यूज

Musk ने हाल ही में रोडस्टर के बारे में चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि कार का डिजाइन अब कंप्लीट हो गया है और इस साल के अंत में इसका अनावरण किया जाएगा साथ ही डिलीवरी अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। मस्क ने दावा किया है कि रोडस्टर एक सेकंड से भी कम समय में 0-60 मील प्रति घंटे की गति हासिल कर लेगी।

नई दिल्ली। Tesla की पॉपुलर Roadster Electric Supercar इस साल के अंत में पेश की जाएगी और इसका प्रोडक्शन अगले साल शुरू किया जाएगा। Tesla के सीईओ Elon Musk ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

Tesla Roadster को लेकर नया अपडेट

Musk ने हाल ही में रोडस्टर के बारे में चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि कार का डिजाइन अब कंप्लीट हो गया है और इस साल के अंत में इसका अनावरण किया जाएगा, साथ ही डिलीवरी अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। मस्क ने दावा किया है कि रोडस्टर एक सेकंड से भी कम समय में 0-60 मील प्रति घंटे की गति हासिल कर लेगी, जो बाजार में वर्तमान में सबसे तेज गति से चलने वाली उत्पादन कारों को पीछे छोड़ देगी।

लॉन्च में हुई देरी

शुरुआती अनावरण के बाद से ही रोडस्टर के विकास में देरी और अटकलबाजी देखी गई है। वाहन के लिए ऑर्डर 2017 में खोले गए थे, जिसकी डिलीवरी 2020 के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि, जैसे ही टेस्ला ने साइबरट्रक सहित अन्य प्रोजेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित किया, रोडस्टर को लेकर काम ठंडे बस्ते में चला गया था।

रोडस्टर के रीडिजाइन के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक ₹स्पेसएक्स रॉकेट थ्रस्टर विकल्प पैकेज₹ को शामिल करना है, जिसके बारे में मस्क का दावा है कि यह कार की एक्सिलरेशन, टॉप स्पीड, ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग क्षमताओं को बढ़ाएगा। इस विकल्प पैकेज में कार के चारों ओर व्यवस्थित 10 छोटे रॉकेट थ्रस्टर्स शामिल होंगे।

क्या आपकी कार हो जाती है ज्यादा गर्म, तो करें ये जरूरी काम, चलेगी कूल-कूल!

कार का ज्यादा गर्म होना इंजन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं यह बीच सड़क कार के खराब होने का कारण बन सकता है, जिसे ठीक कराने में जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। गाड़ी के ओनरशिप को सुचारू और बिना परेशानी का बनाने के लिए, यह अहम है कि आप पहले से ऐसे उपाय करें जो आपके वाहन के तापमान को कंट्रोल में रखें। ज्यादा गर्म होने से संभावित रूप से आपके इंजन के ओवरऑल हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है और जिससे मरम्मत भी महंगी हो सकती है।

कार को गर्म होने से बचाने और ऑप्टिमम इंजन परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए, हम आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और उपाय बता रहे हैं। इन तरीकों को समय रहते लागू करने से, आप अपनी कार के ज्यादा गर्म होने के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं।

नियमित रूप से कूलेंट के लेवल की जांच करें

सुनिश्चित करें कि आपके वाहन का कूलेंट लेवल निर्धारित रेंज के भीतर है। कम कूलेंट लेवल से इंजन में गर्मी निकलने की क्षमता को कम कर सकता है। जिससे इंजन के ज्यादा गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है।

रेडिएटर की जांच करते रहें

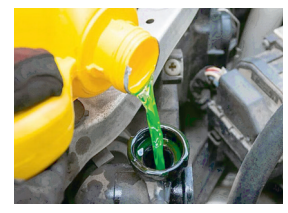

रेडिएटर में किसी भी तरह के रिसाव, जंग या नुकसान के संकेतों के लिए इसकी जांच रेगुलर तौर पर करते रहना चाहिए। गर्मी को कम करने के लिए एक रेडिएटर को अच्छी तरह से मेंटेन रखना जरूरी है। रेडिएटर पर जमा होने वाले मलबे, गंदगी और कीड़ों को हटा दें। एक साफ सतह गर्मी को बेहतर तरीके से कम करती है।

रेडिएटर कैप को सुरक्षित रखें

सुनिश्चित करें कि रेडिएटर कैप को कसकर सील कर दिया गया है। एक ढीला या टूटा हुआ कैप कूलेंट के वाष्पीकरण (उड़ने) को बढ़ावा दे सकती है। जिससे सिस्टम कम असरदार हो जाता है।

कूलिंग फैन की निगरानी करें

जांच लें कि कूलिंग फैन ठीक से काम कर रहा है। एक खराब पंखा हवा के फ्लो को रोक सकता है। जो ज्यादा गर्म करने में योगदान देता है।

ओवरलोडिंग से बचें

अत्यधिक भार आपके वाहन पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे गर्मी पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इंजन पर अनावश्यक तनाव को रोकने के लिए अपनी कार को ओवरलोड करने से बचें।

होण्डा ने दिया फौजी भाइयों को तोहफा! City और Amaze के बाद अब Elevate भी होगी कैंटीन में उपलब्ध

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने देश भर में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट्स (CSD) में Honda Elevate की पेशकश करके भारतीय सशस्त्र बल के सदस्यों को एक तोहफा दिया है। डायमेंशन की बात करें तो ये 4312 मिमी लंबी 1790 मिमी चौड़ी 1650 मिमी ऊंची होने साथ 2650 मिमी व्हीलबेस और 220 मिमी के ग्राउंड क्लीयरेंस में उपलब्ध है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने देश भर में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट्स (CSD) में Honda Elevate की पेशकश करके भारतीय सशस्त्र बल के सदस्यों को एक तोहफा दिया है। कंपनी ने कहा कि Honda City और Amaze के साथ सीएसडी स्टोर्स में Honda Elevate की उपलब्धता प्रीमियम ऑटोमोटिव समाधानों के साथ सशस्त्र बल समुदाय की सेवा के लिए कंपनी के समर्पण पर जोर देती है।

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के उपाध्यक्ष कुणाल बहल ने कहा- हमारे वर्दीधारी नायकों के लिए होंडा एलिवेट की उपलब्धता बढ़ाना एक विशेषाधिकार है। ये पहल उन लोगों को समर्थन देने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है जो हमारे देश की सेवा करते हैं और उन्हें उच्च गुणवत्ता तक पहुंच प्रदान करते हैं।

Honda Elevate में क्या खास?

Honda Elevate एक एक बोल्ड और मस्कुलर डिजाइन का दावा करती है, जिसे 6-स्पीड एमटी और 7-स्पीड सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ एक शक्तिशाली 1.5L i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है।

डिजाइन और डायमेंशन

डायमेंशन की बात करें, तो ये 4312 मिमी लंबी, 1790 मिमी चौड़ी, 1650 मिमी ऊंची होने साथ 2650 मिमी व्हीलबेस और 220 मिमी के ग्राउंड क्लीयरेंस में उपलब्ध है। ये ग्राहकों को बहुत किफायती मूल्य पर ADAS सुरक्षा तकनीक के साथ CVT ऑटोमैटिक और MT ट्रांसमिशन की सुविधा के साथ विकल्पों की एक विस्तृत सीरीज प्रदान करती है।

इंटीरियर

एलिवेट में बेहतरीन इंटीरियर के साथ अच्छा व्हीलबेस, पर्याप्त हेडरूम, घुटने के लिए जगह, लेगरूम और सेगमेंट में बेहतर कार्गो स्पेस मिलता है। इसके विशाल इंटीरियर और होंडा सेंसिंग की एडास तकनीक सहित उन्नत सुरक्षा विशेषताएं आरामदायक और तनाव मुक्त सुरक्षित ड्राइव सुनिश्चित करती हैं।

क्या आपकी जेब पर कम बोझ डालती हैं Kia Seltos, Sonet और Carens? मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर यह बात आई सामने

परिवहन विशेष न्यूज

एक स्टडी से पता चला है कि Kia Sonet Seltos SUV और Carens MPV खरीदने के बाद ग्राहकों को बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट भरनी पड़ती है। किआ ने गुरुवार (29 फरवरी) को तीन प्रमुख मॉडलों पर फोर्ट एंड सुलिवन द्वारा साझा की गई रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि किआ कैरेंस थ्री-रो सेगमेंट में सबसे आगे है।

नई दिल्ली। एक स्टडी से पता चला है कि Kia Sonet, Seltos SUV और Carens MPV खरीदने के बाद ग्राहकों को बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट भरनी पड़ती है। भारत की विकास सलाहकार कंपनियों में से एक, फ्रॉस्ट एंड सुलिवन ने हाल ही में एक विश्लेषण किया जिसके ये परिणाम सामने आए। अध्ययन में कहा गया है कि सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस की रखरखाव लागत उनके सेगमेंट में उपलब्ध अन्य वाहनों के मुकाबलेसबसे कम है।

Kia Carens

किआ ने गुरुवार (29 फरवरी) को तीन प्रमुख मॉडलों पर फोर्ट एंड सुलिवन द्वारा साझा की गई रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि किआ कैरेंस थ्री-रो सेगमेंट में सबसे आगे है। कैरेंस पेट्रोल वर्जन की मेंटेनेंस लागत इसके किसी भी कंपटीटर की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक किफायती है। वहीं, रखरखाव के लिए 26 प्रतिशत कम लागत के साथ डीजल संस्करण और भी अधिक किफायती है।

Kia Seltos

कोरियाई ऑटो दिग्गज का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल किआ सेल्टोस, कम रखरखाव लागत के मामले में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में भी सबसे अच्छा विकल्प बनकर उभरा है। किआ सेल्टोस का पेट्रोल वेरिएंट अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में रखरखाव पर 17 प्रतिशत अधिक बचत कर सकता है, जबकि डीजल वेरिएंट अन्य सेगमेंट लीडर के साथ सबसे कम रखरखाव लागत साझा करता है। न्च के आठ महीनों के भीतर ही एक लाख से अधिक बुकिंग मिल चुकी है।

Kia Sonet

पिछले साल दिसंबर में किआ ने फोर्ट एंड सुलिवन द्वारा किए गए एक और शोध को साझा किया था जिसमें कहा गया था कि सोनेट की अपने सेगमेंट में रखरखाव लागत सबसे कम है। इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट पर रखरखाव लागत 16 प्रतिशत कम और डीजल वेरिएंट पर सेगमेंट औसत की तुलना में 14 प्रतिशत कम है।

हुंडई क्रेटा एन लाइन की शुरू हुई बुकिंग, इतने रुपये देकर पक्की करें डिलीवरी डेट

परिवहन विशेष न्यूज

Hyundai Creta N Line भारतीय बाजार में 11 मार्च 2024 को लॉन्च हो रही है। एक डीलरशिप ने बात करते हुए बताया है कि उन्होने आगामी Creta N Line के लिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाना है। क्रेटा एन लाइन 25000 रुपये की टोकन राशि पर बुक की जा सकती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में 11 मार्च 2024 को लॉन्च हो रही है। इससे पहले ही हुंडई की कुछ चुनिंदा डीलरशिप ने आगामी क्रेटा एन लाइन के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। आइए, कंपनी की इस अपकमिंग एसयूवी और बुकिंग अमाउंट के बारे में जान लेते हैं।

Creta N Line बुकिंग शुरू

एक डीलरशिप ने बात करते हुए बताया है कि उन्होने आगामी Creta N Line के लिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाना है। क्रेटा एन लाइन 25,000 रुपये की टोकन राशि पर बुक की जा सकती है। विचार बदलने पर बुकिंग कैंसिल करके आप इस अमाउंट को वापस भी ले सकते हैं। ऑटोमेकर ने वेब पोर्टल के माध्यम से एसयूवी के लिए आधिकारिक बुकिंग लेना भी शुरू कर दिया है।

डिजाइन अपडेट

Hyundai Creta N Line ब्लैक रूफ के साथ ब्रांड की एन लाइन-स्पेसिफिक सिग्नेचर थंडर ब्लू पेंट स्कीम के साथ आएगी। हुंडई वेन्यू एन लाइन और आई20 एन लाइन के समान, थंडर ब्लू पेंट स्कीम में विभिन्न हिस्सों पर रेड कलर एक्सेंट मिलेंगे।

इसमें दोबारा डिज़ाइन किए गए फ्रंट और रियर बंपर के साथ स्पोर्टियर और अधिक आक्रामक स्टाइल मिलेगा। एसयूवी विभिन्न रंग विकल्पों और दो वेरिएंट विकल्पों में भी उपलब्ध होगी। एसयूवी का एक वेरिएंट N10 होगा।

इंटीरियर

बाहरी हिस्से की तरह, आगामी हुंडई क्रेटा एन लाइन अपने केबिन के अंदर भी विशिष्ट स्टाइल के साथ आएगी। इसमें एक स्पोर्टी ऑल-ब्लैक थीम होगी, जिसमें विभिन्न स्थानों पर रेड स्टिचिंग और इंसर्ट होंगे। उम्मीद है कि एसयूवी डुअल डिस्प्ले सेटअप, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री सराउंड कैमरा, वायरलेस चार्जर और एंबियंट लाइटिंग सहित कई फीचर्स से लैस होगी। इसे 6 एयरबैग के साथ एडास सुइट भी मिलेगा।

क्या है सहज संन्यास

पी.के. खुराना

सहज संन्यास घर छोडने, परिवार छोडने, दुनिया छोडने, कपड़े रंगवाने, सिर मुंडाने या बाल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं, वैसे ही रहें। हम जो काम कर रहे हैं, वो पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, पूरी काबलियत से करें। जो करें वह ऐसा हो जो सबके भले के लिए हो, तो हम संन्यासी हैं। जब हम लालच छोड़ दें, क्रोध छोड़ दें, ईष्र्या छोड़ दें, ऊंच-नीच का विचार छोड़ दें, धोखाधड़ी छोड़ दें, फरेब छोड़ दें तो हम संन्यासी हैं। हमारे कामों से अगर समाज का भला हो जाए, किसी एक का भी भला हो जाए, तो हम संन्यासी हैं'

हमारे देश की खूबी है कि हम धार्मिक लोग हैं, भगवान से डरते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने धर्म के अनुसार बने अपने पूजा स्थलों में जाते हैं, और एक नियत विधि से पूजा करते हैं। इस नियत विधि में जो भी आवश्यक कर्मकांड है, उसे निभाते हैं। अपने-अपने धर्म के संतों, फकीरों के प्रवचन सुनते हैं और आनंदित होते हैं। पूजा-पाठ करना, नियत विधि से पूजा-पाठ करना श्रेष्ठ कर्म है, इससे मन निर्मल होता है, परंतु हममें से बहुत लोग नहीं जानते कि पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन आदि अध्यात्म की प्री-नर्सरी क्लास की तरह है। ये शुरुआती खिलौने हैं। अध्यात्म इससे बहुत आगे की चीज है। आध्यात्मिक होने के लिए बहुत सी सीढियां चढनी पड़ती हैं। हमारी विडंबना यह है कि हमने धर्म को अध्यात्म मान लिया है, जबकि धार्मिक होना अध्यात्म की पहली सीढ़ी मात्र है और जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, उससे ज्यादा बढक़र कोई धार्मिक हो ही नहीं सकता। पूजा-पाठ करना, माला जपना, दान-पुण्य करना, सब अच्छे काम हैं और इनके लाभ से इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी सहायता से आध्यात्मिक हो पाने के रास्ते खुलते चलते हैं, जिसका सीधा स्पष्ट मतलब है कि मंजिल पाना अभी बाकी है।

हम जिस परिवार में जन्मे उससे हमारा धर्म तय हो जाता है और हम जिस देश में रह रहे हों, हमारे धर्म की बहुत सी क्रियाएं उस देश की परंपराओं से प्रभावित हुई हो सकती हैं। भारतवर्ष के हिंदुओं और उनकी धार्मिक मान्यताओं तथा किसी अन्य देश के हिंदुओं और उनकी धार्मिक मान्यताओं में बहुत सी सामान्यताएं होंगी तो कुछ फर्क भी जरूर होगा, जो दोनों देशों की अलग-अलग जीवन पद्धति से प्रभावित होता है। हम किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी पूजा पद्धति में विश्वास रखने वाले हो सकते हैं। इससे हमारी आध्यात्मिकता पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आध्यात्मिकता का यह विश्वास है कि हम पूजा स्थल से बाहर कैसा जीवन बिताते हैं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारी सोच कैसी है, इससे तय होता है कि हम आध्यात्मिक हैं या नहीं। जब हम इसकी गहराई को समझ लेते हैं तो हम आध्यात्मिकता की दिशा में मजबूती से आगे बढना शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उनकी बेहतरी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। उनकी खुशियों के लिए अपने सपने तक बलिदान कर देते हैं। खुद टूटी चप्पल पहनकर भी बच्चों के लिए नए जूते लाने से गुरेज नहीं करते। यह निश्छल-निस्वार्थ प्रेम जब सबके लिए उपलब्ध हो जाता है तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम-भाव से निभाने लग जाते हैं, जब हम निश्छल भाव से अपने कत्र्तव्यों का निर्वहन आरंभ कर देते हैं तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। हम किसी भी धर्म को मानते हों, कहीं भी रहते हों, हमारी वेशभूषा कैसी भी हो, बोली कोई भी हो, हम आध्यात्मिक हो गए तो सारे फर्क मिट जाते हैं। फिर विरोध खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, हिंसा खत्म हो जाती है। विभिन्न संप्रदायों के बीच मतभेद हो सकते हैं, आध्यात्मिकता में कोई मतभेद नहीं है। परमात्मा एक है, पर उस तक पहुंचने के रास्ते बहुत से हैं, इसलिए कोई दूसरा रास्ता गलत नहीं है।

वैतरणी पर पुल बन जाए, हम उसे नाव से पार करें, तैर कर पार करें या हवाई सेवा की सहायता लेकर पार करें, मतलब तो उस पार जाने से है, साधन कुछ भी हो सकता है। परमात्मा एक है, रास्ते कई हो सकते हैं, हैं ही। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि हम सबके प्रति दया का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, जहां तक संभव हो, निस्वार्थ भाव से सहायता करें। हम खुद को बदलें, हमारे अंदर के परिवर्तन से ही सब कुछ बदलेगा। हमारा नजरिया बदलेगा तो हम बदलेंगे। हम बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगी, हमारी दुनिया नहीं बदलेगी। हमारे संपर्क में आने वाले लोग हमारी दुनिया हैं। हम बदल जाएंगे तो शायद हम उन लोगों में बदलाव ला सकेंगे जो हमारे संपर्क में आते हैं। हम ही नहीं बदले तो बाकी सब बदल भी जाए तो भी हमारे लिए वह बदलाव अर्थहीन ही रहेगा।

आध्यात्मिक हो जाएं तो पूरा ब्रह्मांड हमें परमात्मा की स्तुति करता हुआ नजर आता है। गुरु नानक देव जी ने क्या खूब कहा है कि यह पूरा आकाश एक बड़े थाल की तरह है जिसमें सूरज और चंद्रमा नाम के दो दीपक जल रहे हैं और तारामंडल मोतियों के समान जगमग-जगमग कर रहा है। रंग-बिरंगे फूलों की सुगंध से भरपूर हवा ही मानो धूप-दीप-बत्ती बन गई है। ऐ परमात्मा, तेरी आरती कितनी सुंदर हो रही है! जब पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा की स्तुति कर रहा हो तो कंकर-पत्थरों के जोड़ से बने पूजा स्थलों का भेद खत्म हो जाता है, तब हम किसी को डराते नहीं। तब हम किसी से घबराते नहीं। तब हममें किसी से वैर-विरोध की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब तलवारें अर्थहीन हो जाती हैं। बुद्ध जंगल से जा रहे थे और अंगुलीमाल ने उन्हें ठहर जाने को कहा तो बुद्ध ने सिर्फ इतना ही कहा था कि लो मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? और इस एक सवाल ने एक निर्मम डाकू को संत बना दिया। यह आध्यात्मिकता का कमाल है।

आध्यात्मिकता का मतलब है – सहज संन्यास।

सहज संन्यास घर छोडने, परिवार छोडने, दुनिया छोडने, कपड़े रंगवाने, सिर मुंडाने या बाल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं, वैसे ही रहें। हम जो काम कर रहे हैं, वो पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, पूरी काबलियत से करें। जो करें वह ऐसा हो जो सबके भले के लिए हो, तो हम संन्यासी हैं। जब हम लालच छोड़ दें, क्रोध छोड़ दें, ईष्र्या छोड़ दें, ऊंच-नीच का विचार छोड़ दें, धोखाधड़ी छोड़ दें, फरेब छोड़ दें तो हम संन्यासी हैं। हमारे कामों से अगर समाज का भला हो जाए, किसी एक का भी भला हो जाए, तो हम संन्यासी हैं।

उसके लिए किसी बाहरी प्रतीक की आवश्यकता नहीं है, किसी बाहरी निशानी की आवश्यकता नहीं है। हां, यह समझना आवश्यक है कि यदि कोई प्रतीक हमें उच्च मानसिक अवस्था में पहुंचाता है तो बिना कारण उसे अंधविश्वास न मानें या उसे न नकारें। उदाहरण के लिए तिलक हमारे पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है और हमें सही फैसले लेने में सहायक होता है। चुटिया, हमें अनंत ब्रह्मांड से जोड़ती है। ये साधन हैं, औजार हैं, टूल हैं प्रकृति से जुडने के लिए, ब्रह्मांड से जुडने के लिए। इन साधनों का उपयोग न गलत है, न बुरा और न दिखावा। हां, सिर्फ दिखावे की मंशा से इनका सहारा लेना इनका दुरुपयोग है। मैं खुद संन्यास आश्रम में हूं। न मैंने परिवार छोड़ा है, न दुनिया छोड़ी है, न काम-धंधा छोड़ा है। स्पिरिचुअल हीलर के रूप में समाज सेवा का आनंद ही और है और इससे आने वाला धन इस काम को और आगे बढ़ाकर बृहत्तर समाज सेवा में लग रहा है, मेरे लिए यही संन्यास है। इस सहज संन्यास ने ही मुझे हैपीनेस गुरू से आगे बढक़र सिद्धगुरू बनाया है। इस सहज संन्यास को नमन है।

संपादक की कलम से

कांग्रेस खुद पर अफसोस करे

कांग्रेस खुद पर अफसोस या गुस्सा करे, अहंकार की दौलत में बिक रहा जमाना। जाहिर है हिमाचल से राज्यसभा की यात्रा ने एक सरकार के वजूद को छील दिया और इस छिछालेदर में सारी खुन्नस निकल गई। राजनीति अपनी बस्ती नहीं चुन सकती, तो अपनी ही अस्थि उठानी पड़ेगी, वरना भाजपा के कुल 25 विधायकों के सामने कांग्रेस के चालीस इतने सक्षम थे कि अभिषेक मनु सिंघवी यहां से राज्यसभा का तिलक लगाकर लौटते, मगर लुटिया डूबी जहां आशाएं तैर रही थीं। इस गिनती पर कौन भरोसा करे जिसने भाजपा के हर्ष में अपनी तौहीन कबूल की। आश्चर्य यह कि जिस अकड़ से सत्ता चल रही थी, उसकी हड्डी पसली एक कर दी, लेकिन आत्मबोध का आचरण खुद को साबित नहीं कर सका। सुलगती सूलियों को तिनके समझकर, कांग्रेस ने अपने ही हाथों को जलाया इस कद्र। ऐसे में भाजपा का जीतना जनादेश की गवाही नहीं, लेकिन कांग्रेस का हारना जगहंसाई जरूर है। कौनसा शिखर और कौनसी तोपें थीं इस दुर्गा की, कयामत घर से निकली और सारे गुरूर को जला गई। ऐसे में गलत कौन? जनता जिसने कांग्रेस को सत्ता सौंपी या वो जो बागी हो गए। क्यों न इस सल्तनत को दोषी मानें जो हिमाचल में निरंकुश और दिल्ली में अंधी थी। कब कांग्रेस अपनी हैसियत से 'आलाकमान' की हेकड़ी से बाहर नेतृत्व का कौशल दिखा पाएगी। यहां वह नेतृत्व भी हारा जिसने हिमाचल में सुक्खू सरकार का मौजूदा आकार बनाया और वह सत्ता भी हारी जिसने यारों का सहारा बनाया। एक एक करके गिनेंगे तो कितने कैबिनेट रैंक बिखर गए और बिखरा वह असंतुलन जो हिमाचल में कांग्रेस को संगठित नहीं कर पाया। आश्चर्य यह कि मुख्यमंत्री के गृह जिला से तीन विधायकों ने बगावत की, तो अपनी ही पार्टी को हराने में सुधीर शर्मा व राजिंद्र राणा ने शहादत दी। एक आसान सी जीत में अगर सुक्खू सरकार फिसल गई, तो सरकार के असंतुलन ही खा गए सरकार को। 'चादर फट गई पांव में नाखून बढ़े थे, शहनशाह की किस्ती में छेद बड़े थे।' अब एक बदसूरत तस्वीर में कांग्रेस का तामझाम और दिल्ली का दरबार खुद को होश में लाने के लिए प्रयासरत है। चोट खाने के बाद दिल का हाल पूछा जा रहा है, अपनी नब्ज को दूसरे हाथ में देकर मापा जा रहा है। यानी छह विधायक छंट गए, विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद छोड़ दिया और कितने सबूत चाहिएं कि आग किस कद्र लगी है। कांग्रेस को खुद पर भरोसा कब होगा। हिमाचल में सरकार का गठन जिस तरह हुआ, उसमें नालायकी, अहंकार, टकराव और उपेक्षा थी। फैसलों की फेहरिस्त में अपने ही विधायकों के अपमान अगर जुड़ रहे थे, तो कहीं बंदूक के साये सत्ता को अपने नशे की हिफाजत की चिंता थी। पहले मंत्रिमंडल के आकार में और फिर इसके प्रकार में कान ही तो पकड़े गए। जिस कांगड़ा ने दस विधायक दिए, उसका सबसे क्षमतावान चेहरा इतना मजबूर किया कि वह आज सरकार के विरुद्ध तलवार बन गया। मंत्रियों को मजदूर और गैर विधायकों को अंगूर खिलाकर आत्मसंतुष्टि तो हो सकती है, लेकिन सरकारें यूं नहीं चलतीं। आश्चर्य यह कि सरकार के बीच खड़े राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा व तमाम विक्षुब्ध विधायकों की न कोई सुन रहा था और न ही सुनना चाहता था। बहरहाल कांग्रेस 'आलाकमान' को इतना होश तो आया कि पर्यवेक्षक शिमला की गलियों में अपनी ही सरकार को ढूंढ रहे हैं। जनता ने तश्तरी पर सौंपी थी जो सत्ता, आज उसकी लाज बचाने के लाले पड़े हैं। इस दृश्य में भाजपा थी ही नहीं, लेकिन उसे अगर सियासी धाम परोसी गई, तो कांग्रेस को अब जनता क्यों अपना नसीब सौंपे। जिन्हें इंतकाम लेना था, ले लिया। जिन्होंने अहंकार में चूर होकर जितनी सरकार चलानी थी, चला ली, लेकिन बहुत कुछ खोना पड़ा हिमाचल को। पहली बार अस्थिरता के दामन में हिमाचल का लोकतांत्रिक विश्वास चकनाचूर हो रहा है। यह वह प्रदेश है जो तीसरी शक्ति को हमेशा पटकनी देता रहा ताकि कांग्रेस बनाम भाजपा के बीच सियासी तासीर सुदृढ़ हो, लेकिन यहां तो यह भ्रम भी टूट गया।

राय

'अंतरात्मा' की चुनावी परंपरा

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पालाबदल और क्रॉस वोटिंग का सबसे सनसनीखेज और विवादास्पद उदाहरण 1969 का राष्ट्रपति चुनाव था। 16 अगस्त, 1969 को पांचवें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। लोकसभा के पूर्व स्पीकर नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनकी उम्मीदवारी से सहमत नहीं थीं, लिहाजा उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ, अपने उम्मीदवार के तौर पर, लोकप्रिय मजदूर यूनियन नेता वीवी गिरि को चुनाव मैदान में उतार दिया। गिरि ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। तब स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और विपक्ष के अन्य दलों ने सीडी देशमुख को अपना साझा उम्मीदवार बनाया। वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे। उस दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'अंतरात्मा' के आधार पर मतदान करने का आह्वान किया था। नतीजा यह हुआ कि वीवी गिरि को 4,20,077 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को 4,05,427 वोट हासिल हुए। वीवी गिरि राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। इस स्तर का वह एकमात्र चुनाव रहा, क्योंकि उसके बाद 'अंतरात्मा' की आवाज पर राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन पालाबदल, पलटुओं, क्रॉस वोटिंग के चुनावों की लंबी परंपरा हमारे देश में रही है। इसे स्वतंत्र बौद्धिक, वैचारिक मतदान का नाम दिया गया अथवा घोड़ों की तरह विधायक खरीदे-बेचे गए या राजनीतिक दल के दायरे और उनकी निष्ठाएं बदलती रहीं। यह मुद्दा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के दौर में भी उठा, जब गुप्त मतदान के बजाय खुले मतदान की पैरवी की गई। अंततः 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कानून मंत्री अरुण जेतली ने 'खुले मतदान' पर विधेयक संसद में पेश किया और वह कानून बना। समस्या जस की तस रही और अब 2024 के राज्यसभा चुनाव में उप्र, हिमाचल, कर्नाटक आदि राज्यों में विधायकों ने खुल कर 'क्रॉस वोटिंग' की। बयान दिए जाते रहे कि उन्होंने 'अंतरात्मा' की आवाज पर, जिसे योग्य समझा, उसके पक्ष में वोट किया। दरअसल इसके साथ दलबदल की समस्या भी जुड़ी है। उसे रोकने पर भी कानून है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के साथ-साथ विधायकों के दलबदल भी सामने आए हैं। उनके खिलाफ संसदीय अथवा विधानसभा के स्तर पर कार्रवाई बहुत लंबी चलती है, देरी भी होती है या आगामी चुनाव का समय भी करीब आ जाता है। फिर कानून के फायदे क्या हैं? महाराष्ट्र का उदाहरण सबसे ताजा है। उप्र में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग ही नहीं की, बल्कि पार्टी भी बदल ली। उनमें विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय भी एक हैं। इसका असर अमेठी, रायबरेली, अयोध्या समेत 7 लोकसभा सीटों पर पडना निश्चित है। यही नहीं, गुजरात से छह बार के सांसद एवं पूर्व रेल राज्यमंत्री नारायण राठवा अपने बेटे समेत कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष वासवराज पाटिल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ और राजद की विधायक संगीता कुमारी ने भी दलबदल कर भाजपा का पाला चुना है। चर्चा है कि भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़वाने का आश्वासन दिया है। दलबदल या क्रॉस वोटिंग नैतिकता या किसी ईमान का सवाल नहीं है और न ही जनता के साथ धोखा है। जनता अगले चुनाव में अपना जनादेश देकर उन्हें सही ठिकाने लगा सकती है, लेकिन इनसे सरकारें अस्थिर होती हैं और अंततः प्रभाव जनता पर ही पड़ता है। अब अहम सवाल यह है कि क्या ऐसा कानून बनेगा कि एक दल से जीतने के बाद पाला न बदला जा सके।

सही रंग की पहचान

बहुत दिन से हमें रंगों की तमीज करनी भूल गई! काला रंग सदा डराने वाला लगता था, आज कितना अपना-सा लगने लगा है। काला रंग जो रात के उतरने का सूचक होता है। यह रंग अंधेरे का सहोदर है। आज जिस आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसकी शुरुआत ही कभी एक आधी रात को किसी जननायक ने अपनी क्षीणकभीर वाणी से की थी। 'रात के बारह बज गए। अब देश में आजादी की नई सुबह होगी। सदियों की गुलामी भरा यह काला अंधेरा छंट जाएगा। फिर क्षितिज पर उषा की लालिमा उभरेगी। नया सवेरा नई आजाद सांसों का ध्वजवाहक होगा।' काला रंग विदा होगा, नए सूरज की सफेदी इस धरा पर उतरेगी। हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, और हर बच्चे के हाथ में किताब सी सफेदी। इस सफेदी से सब अंधेरे भगौड़े हो जाएंगे। अतीत की कालिख कचरे के उस डिब्बे में डाल दी जाएगी, कि जिसके पास कभी सुबह की सफेदी फटकना न चाहेगी। वायदे बहुत से वायदे। लेकिन इतना वक्त बीत गया कि अब तो हम इस बीतते वक्त का अमृत महोत्सव भी मनाने चले। लेकिन यह कैसा वक्त बीता कि काला अंधेरा और भी पांव पसार कर देश में जलते चिराग बुझाता चला गया। सफेद रंग का, उसके धवल उजलेपन का अवमूल्यन हो गया। नेताओं के धवल कुर्ते पायजामे और कशतीनुमा सफेद टोपियां गाहे-बगाहे रंग बदलती रहीं, लेकिन उन्होंने एक बार हाथ आई कुर्सियों की सवारी नहीं छोड़ी, बल्कि इन पर आधिपत्य जमाए अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान वे इसे अपने नाती-पोतों के लिए सुरक्षित करने लगीं।

नाती-पोते भी ऐसे कि जिन्हें इतनी समझ भी नहीं कि इस देश ने दो सौ बरस की गुलामी इंग्लिशस्तान की भुगती थी, या अमरीका की? अब भला उन्हें कैसे समझाएं कि भौगोलिक गुलामी तो तुमने अंग्रेजों की भुगती थी, अब 'एक दुनिया एक मंडी' के नाम पर तुम व्यावसायिक गुलामी अमरीका जैसे धनी मानी देशों की भुगत रहे हो। विदेशी थैलीवानों के निवेश की चाह ने इस आर्थिक गुलामी का भूमंलीकरण कर दिया, सुना क्या? जी हां, रंगों की पहचान की गड़बड़ यहीं से होती है। चले थे सफेदी भरी सुबह की तलाश में, और यहां कभी न खत्म होने वाली रात का अंधेरा सुबह हो जाने का भ्रम देने लगा। हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और हर नए जन्मे के हाथ में किताब नई सुबह की रौशनी का आभास नहीं, देश में गहराते अंधेरे में नारों की मशाल बन गई। यह मशाल हर पांच साल के बाद चुनाव के दिनों के करीब क्यों एकाएक भक्क से जल उठती है? चुनाव परिणामों के बाद कुर्सियां बंट जाएं तो यह मशाल क्यों भव्य अट्टालिकाओं का आतिशदान बन जाती है? हम रंगों के मसीहा से पूछना चाहते हैं, कि न उभरने दो, करोड़ों लोगों के बीच में से ऐसे सवाल कि जिनका जवाब चुनावी भाषणों के पास नहीं है। क्यों न इस प्रश्नावली से निकलने की बजाय हम काले रंग को सुबह के सफेद राजसी दोशाले से समेट कर इसे एक समन्वयवादी गरिमा प्रदान कर दें? जानते हो जिंदगी का सच काले को सफेद में बदल देना नहीं है, एक नए मटमैले रंग का स्वीकार है, जहां कतार में खड़ा आखिरी आदमी एक दीर्घ उच्छवास भर कर कह सके, यहां यूं ही चलता है भय्या! क्या हम यह नया सच स्वीकार कर लें कि यहां सूरज के रथ में जुता सातवां घोड़ा उसी अंधेरे का वारिस है, जो दूसरे छह घोड़ों को भी चलने की प्रेरणा देता है। जवाब नहीं मिला। पौन सदी गुजर गई, क्यों न इस बात का अमृत महोत्सव मना लें कि भ्रष्टाचारी देशों के सूचकांक में हमारा दर्जा और भी गिरावट भरा हो गया है। यह बात तो एक अकाट्य सत्य हो गई कि इस देश में उचित सम्पर्क सूत्र के बिना कोई काम अपनी मंजिल की ओर नहीं सरकता।

सुरेश सेठ

गहन विचार

घातक है कैंसर पीड़ितों की संख्या

इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा वैश्विक स्तर पर कैंसर की व्यापकता पर जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में 75 वर्ष की आयु से पहले कैंसर से मरने का जोखिम 7.2 फीसदी है। अधिकांश देश सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के हिस्से के रूप में प्राथमिकता वाले कैंसर और उपशामक देखभाल सेवाओं को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं करते हैं

कैंसर अब दुनिया भर में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण बन चुका है। कैंसर रोग की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में कैंसर रोगियों के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य कैंसर संस्थान चलाने का फैसला किया है। इसका लाभ भविष्य में कैंसर रोगियों और उनके परिजनों को मिलेगा और रोगियों को प्रदेश के बाहर जाकर उपचार करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। स्पष्ट है कि राज्य सरकार कैंसर पीड़ितों की बढ़ती संख्या को लेकर न केवल चिंतित है बल्कि कैंसर उपचार की दिशा में जिला अस्पतालों और आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में कैंसर डे केयर सेंटर और आईजीएमसी शिमला में उन्नत रेडियोथेरेपी उपचार प्रदान करने के लिए लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन की स्थापना भी करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया है। शिमला के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल के लिए अब 25 करोड़ रुपए की लागत से लीनियर एक्सेलरेटर मशीन स्थापित करने की तैयारियां जोरों पर हैं। यह आधुनिक मशीन अमरीका से आई है। चूंकि प्रदेश में कैंसर मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है लिहाजा यह नई मशीन रेडिएशन देने में काम आएगी। ऐसा अनुमान है कि हिमाचल में प्रतिवर्ष 2000 लोग कैंसर की चपेट में आ रहे हैं।

शिमला के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल की अगर बात की जाए, तो यहां एक साल के अंदर 650 ब्रेस्ट कैंसर के ही मरीज ईलाज हेतु आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार महिलाओं में सबसे अधिक गर्भाशय, स्तन और अंडाशय कैंसर देखने को मिलते हैं जबकि पुरुष सबसे अधिक फेफड़े, गले और मुंह के कैंसर की चपेट में आते हैं। गुदा एवं गाल ब्लैडर कैंसर के भी मामले सामने आ रहे हैं। अभी गत चार फरवरी को पूरे विश्व में कैंसर दिवस मनाया गया है। लिहाजा यह जरूरी है कि हिमाचल सहित भारत के नागरिकों में कैंसर जैसे नामुराद रोग के प्रति जागरूकता का संचार किया जाए। कैंसर कई तरह का होता है और हर कैंसर के होने के अलग-अलग कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे भी हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा किसी को भी हो सकता है। इनमें वजन बढना या मोटापा, अधिक शारीरिक सक्रियता न होना, एल्कोहल और नशीले पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना, कैंसर में पौष्टिक आहार न लेना, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल न करना इत्यादि है। किसी गंभीर बीमारी के कारण भी आपको कैंसर हो सकता है। शरीर में कोशिकाओं के समूह की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर का कारण माना जाता है। कैंसर के सौ से भी अधिक रूप हैं। इनमें स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेन कैंसर, बोन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, पेंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, त्वचा कैंसर, स्टमक कैंसर, थायरॉड कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर इत्यादि मुख्य हैं। भारत में कैंसर के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुमानित वैश्विक कैंसर आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में 14.1 लाख से अधिक नए कैंसर के मामले सामने आए और इसकी वजह से 9.1 लाख से अधिक मौतें हुईं। वहीं वैश्विक स्तर पर दो करोड़ नए कैंसर के मामले देखे गए। डब्ल्यूएचओ की कैंसर एजेंसी आइएआरसी अर्थात्इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने 185 देशों और 36 तरह के कैंसर का विश्लेषण कर आंकड़े जारी किए है। आंकड़ों में कैंसर से मृत्यु का जोखिम यूरोप में सबसे अधिक 11.5 प्रतिशत देखा गया। एशिया 9.3 प्रतिशत के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर है। आइएआरसी के अनुसार भारत में नए मामलों में सबसे अधिक 27 प्रतिशत स्तन कैंसर के मामले थे। इसके बाद सर्वाइकल कैंसर 18 प्रतिशत महिलाओं में सबसे ज्यादा देखा गया। पुरुषों में होंठ, ओरल कैविटी और फेफड़े के कैंसर के मामले सबसे अधिक देखे गए। वहीं वैश्विक तौर पर महिलाओं में स्तन कैंसर दूसरा 11.6 प्रतिशत सबसे आम तौर पर होने वाला कैंसर है और वैश्विक कैंसर से होने वाली मौतों में इसका योगदान लगभग सात प्रतिशत है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) द्वारा वैश्विक स्तर पर कैंसर की व्यापकता पर जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में 75 वर्ष की आयु से पहले कैंसर से मरने का जोखिम 7.2 फीसदी है। डब्ल्यूएचओ ने 115 देशों के सर्वेक्षण परिणाम भी प्रकाशित किए हैं जिसमें बताया गया है कि अधिकांश देश सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के हिस्से के रूप में प्राथमिकता वाले कैंसर और उपशामक देखभाल सेवाओं को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं करते हैं।

वर्ष 2022 में, अनुमानित 20 मिलियन नए कैंसर मामले सामने आए थे और 9.7 मिलियन मौतें हुईं। कैंसर निदान के बाद 5 वर्षों के भीतर जीवित रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 53.5 मिलियन थी। लगभग 5 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर हो जाता है, लगभग 9 में से 1 पुरुष और 12 में से 1 महिला की इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (यूआईसीसी) के प्रमुख डॉ. कैरी एडम्स के मुताबिक वैश्विक कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य इस रोग की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने, निदान, उपचार और उपशामक देखभाल के द्वारा कैंसर की घटनाओं, रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना और एक परिभाषित आबादी में कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कैंसर रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए थीम 'क्लोज द केयर गैप : एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर' को चुना गया है, ताकि आम नागरिकों में यह भरोसा पैदा किया जा सके कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ा जा सकता है।

मैन्यूफैक्चरिंग ने किया कमाल, विकास दर आठ के पार

परिवहन विशेष न्यूज

कृषि सेक्टर में गिरावट और सर्विस सेक्टर के स्थिर प्रदर्शन के बावजूद जीडीपी आंकड़ें ने चौंकाया। अक्टूबर से दिसंबर 2023 में देश की अर्थव्यवस्था में 8.4 फीसद की विकास दर हासिल करने में मैन्यूफैक्चरिंग खनन और कंस्ट्रक्शन उद्योग ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। इन तीनों में मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लगातार दूसरी तिमाही में भी दोहरे अंक में (11.6 फीसद) वृद्धि दर्ज की है।

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2023) में देश की अर्थव्यवस्था में 8.4 फीसद की विकास दर हासिल करने में मैन्यूफैक्चरिंग, खनन और कंस्ट्रक्शन उद्योग ने सबसे अहम भूमिका निभाई है।

इन तीनों में मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लगातार दूसरी तिमाही में भी दोहरे अंक में (11.6 फीसद) वृद्धि दर्ज की है जो बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ रहा है। मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश बढ़ने का मतलब है कि यह देश में संपत्ति का निर्माण हो रहा है और लोगों को ज्यादा रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो रहा है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के इस डाटा को अधिकांश विशेषज्ञों ने उम्मीद से भी बेहतर बताया है। साथ ही विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) की विकास दर (6.5 फीसद) और जीडीपी की विकास दर में बढ़ते अंतर को लेकर भी आश्चर्य जताते हुए कहा है कि इसे लंबे समय तक बना कर नहीं रखा जा सकता।

देश की इकोनमी लगा सकती है 7-8 फीसद की छलांग

एनएसओ ने अर्थव्यवस्था को लेकर जो आंकड़े पेश किये हैं उससे यह भी पता चलता है कि कृषि क्षेत्र की विकास दर के खास नहीं रहने के बावजूद देश की इकोनमी 7-8 फीसद की छलांग लगा सकती है। कृषि सेक्टर में इस तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2023) में 0.8 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इस सेक्टर में 5.2 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब साफ है कि इस साल रबी की पैदावार उम्मीद से खराब रही है, हालांकि अभी तक सरकारी एजेंसियां इस बात से इनकार करती रही हैं।

बहरहाल, इस अवधि में मैन्यूफैक्चरिंग की विकास दर 11.6 फीसद रही है जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में इसमें 4.8 फीसद की गिरावट हुई थी। पिछले वर्ष जहां लगातार दो तिमाहियों में इस सेक्टर में गिरावट हुई थी वहीं इस साल लगातार दो तिमाहियों में इसकी वृद्धि दर दोहरे अंक में रहने का संकेत मिल रहा है।

कंस्ट्रक्शन में 9.5 फीसद की वृद्धि

कंस्ट्रक्शन में इस साल भी 9.5 फीसद की वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष भी यहीं वृद्धि दर

थी। बिजली, गैस, जलापूर्ति सेक्टर की वृद्धि दर इस दौरान क्रमशः 9 फीसद और 8.7 फीसद रही है। दोनों तरह के सर्विस सेक्टर (वित्तीय और ट्रेड, होटल आदि) की वृद्धि दर सात फीसद से नीचे बनी हुई है और इनका प्रदर्शन पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले कमतर रहा है, यह सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। देश की इकोनमी में सर्विस सेक्टर की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी के बावजूद सात फीसद की विकास दर को असंतोषजनक माना जाएगा।

एनएसओ ने पूरे वित्त वर्ष (2023-24) के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर के 7.6 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। यह एनएसओ का दूसरा अनुमान है। पहले इसके 7.3 फीसद रहने की बात कही गई थी। एनएसओ के मुताबिक तीसरी तिमाही में जीडीपी का आकार 43.72 लाख करोड़ रुपये की रही है जो अक्टूबर-दिसंबर, 2022 के 40.35 लाख करोड़ रुपये से 8.4 फीसद ज्यादा रही है। जबकि पूरे वर्ष के दौरान जीडीपी का आकार 172.90 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 2022-23 के मुकाबले 7.6 फीसद ज्यादा रहेगी। प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,10,679 रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 2022-23 में 1,94,970 रुपये रही थी।

खरीफ मौसम में भी नहीं महंगे होंगे उर्वरक, खाद सब्सिडी के रूप 24 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी

केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ मौसम में भी उर्वरक नहीं महंगे होंगे। कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को खाद सब्सिडी के रूप में 24 हजार 420 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से किसानों को रियायती एवं किफायती मूल्य पर उर्वरक पहली अप्रैल से 30 सितंबर तक मिलते रहेंगे। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नईदिल्ली। यूरिया समेत अन्य उर्वरकों के मूल्य में खरीफ मौसम में भी वृद्धि नहीं होगी। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिछले वर्ष के मूल्य पर ही इस साल भी उर्वरक बेचने का निर्णय लिया है और किसानों को मिलने वाली उर्वरक सब्सिडी को बरकरार रखा है।

खाद सब्सिडी के लिए मिली मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को खाद सब्सिडी के रूप में 24 हजार 420 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से किसानों को रियायती एवं किफायती मूल्य पर उर्वरक पहली अप्रैल से 30 सितंबर तक मिलते रहेंगे। डीएपी का 50 किलो का एक बैग 1,350 रुपये, एनपीके का बैग 1,470 रुपये एवं एमओपी का बैग 1,677 रुपये में मिलता है।

तीन नए उर्वरकों को किया शामिल

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत तीन नए उर्वरकों को भी शामिल किया गया है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर के अनुपात अलग-अलग हैं, जिनके इस्तेमाल से मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बना रहेगा और पैदावार में भी वृद्धि होगी।

उल्लेखनीय है कि उर्वरक सब्सिडी की दरें वार्षिक या द्विवार्षिक आधार पर निर्धारित की जाती हैं। खरीफ वर्ष 2024 में नाइट्रोजन के लिए 47.02 रुपये, फास्फोरस के लिए 28.72 रुपये, पोटाश के लिए 2.38 रुपये और सल्फर के लिए 1.89 रुपये प्रतिकिलो सब्सिडी निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ उर्वरकों के लिए फ्रेट सब्सिडी भी दी जाती है। इससे किसानों को पुरानी दर पर ही खाद मिलते हैं।

बदल गए सोने-चांदी के रेट, जानें अब कितनी है आपके शहर में गोल्ड प्राइस

आज भी देश में सोने-चांदी के रेट में बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के नए दाम जारी हो गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर की वजह से हर शहर में इनकी कीमत अलग होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोने-चांदी की कीमत क्या है?

नई दिल्ली। आज फरवरी महीने खत्म हो गया है। महीने के आखिरी दिन देश के सभी शहरों में सोने-चांदी के नए दाम जारी हो गए हैं। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की वजह से सभी शहरों में इनके दाम अलग होते हैं।

चलिए, जानते हैं कि आज आपके शहर में गोल्ड की कीमत क्या है।

क्या है आपके शहर में सोने का रेट

दिल्ली में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,990 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,830 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,830 रुपये है।

चैन्नई में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,380 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,830 रुपये है।

हैदराबाद में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 62,830 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,990 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरेट, 10 ग्राम सोना 63,990 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 62,880 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 63,990 रुपये है।

नागपुर में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 62,830 रुपये है।

सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 62,880 रुपये है।

पुणे में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 62,830 रुपये है।

केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 63,830 रुपये है।

बैंगलोर में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 62,830 रुपये है।

दूरसंचार कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर के मुनाफे पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

आयकर विभाग ने राजस्थान कर्नाटक और बांबे हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की थी। जिसमें भारती एयरटेल के वितरकों या फ्रेंचाइजी को प्री-पेड कूपन और सिम कार्ड बेचने से हुई आय से जुड़ा मामले शामिल है। कोर्ट ने कहा कि करदाता दूरसंचार कंपनियां वितरकों या फ्रेंचाइजी द्वारा तीसरे पक्ष यानी ग्राहकों से प्राप्त भुगतान में आय/लाभ पर टीडीएस के लिए कानूनी दायित्व के तहत बाध्य हीं होंगे।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियां ग्राहकों को प्री-पेड कूपन और सिम कार्ड बेचने से वितरकों या फ्रेंचाइजी को हुए लाभ पर टीडीएस के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने बुधवार को आयकर विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल की तरफ से दायर अपीलों पर यह अहम फैसला सुनाया।

क्या है मामला

यह मामला उपभोक्ताओं को प्री-पेड कूपन और सिम कार्ड बेचने से भारती एयरटेल के वितरकों या फ्रेंचाइजी को हुई आय पर आयकर अधिनियम, 19611 की धारा 194-एच के तहत टीडीएस की देनदारी से संबंधित है। आयकर विभाग ने दावा किया था कि वितरकों द्वारा अर्जित मुनाफा करदाता और फ्रेंचाइजी या वितरकों के बीच समझौते के तहत निर्धारित दूरसंचार फर्म द्वारा एक एजेंट को देय कमीशन है।

वितरकों के लाभ पर TDS काटना जरूरी नहीं

जस्टिस खन्ना ने पीठ की तरफ से फैसला लिखते हुए कहा कि हमारा मत है कि करदाता दूरसंचार कंपनियां वितरकों या फ्रेंचाइजी द्वारा तीसरे पक्ष यानी ग्राहकों से प्राप्त भुगतान में आय/लाभ पर टीडीएस के लिए कानूनी दायित्व के तहत बाध्य हीं होंगे। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 194-एच इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है। यह धारा स्त्रोत पर कर कटौती को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाती है। आयकर विभाग ने राजस्थान, कर्नाटक और बांबे हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की थी। उच्च न्यायालयों ने कहा था कि आयकर अधिनियम की यह धारा विचाराधीन परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है।

रबी सीजन में सरकार ने 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीदने का रखा लक्ष्य, धान की खरीद के लिए भी तय किया टारगेट

कृषि मंत्रालय के रिकार्ड उत्पादन अनुमान के बावजूद कम गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। विचार-विमर्श के बाद आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान गेहूं की खरीद का अनुमान 3.0-3.2 करोड़ टन के बीच तय किया गया। रबी सीजन में धान खरीद का लक्ष्य 90 लाख टन से एक करोड़ टन के बीच तय किया है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। सरकार ने 2024-25 के रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान तीन से 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है। खास बात यह है कि कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में 11.4-11.5 करोड़ टन रिकार्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है, लेकिन इसके बावजूद गेहूं खरीद का लक्ष्य बहुत कम तय किया गया है।

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श के बाद लक्ष्य तय किया गया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विचार-विमर्श के बाद, आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान गेहूं की खरीद का अनुमान 3.0-3.2 करोड़ टन के बीच तय किया गया।

धान खरीद का लक्ष्य 90 लाख टन

गेहूं के अलावा मंत्रालय ने रबी सीजन के लिए चावल के मामले में धान खरीद का लक्ष्य 90 लाख टन से एक करोड़ टन के बीच तय किया है। सरकार ने रबी मोटे अनाज/बाजरा (श्री अन्न) के लिए छह लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है।

बैठक में केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फसलों के विविधीकरण और आहार पैटर्न में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। 2023-24 सीजन में सरकार ने 3.415 करोड़ टन लक्ष्य के मुकाबले 2.62 करोड़ टन गेहूं की खरीद की।

2022-23 में गेहूं की खरीद का लक्ष्य 4.44 करोड़ टन तय किया गया था, लेकिन उत्पादन में गिरावट के चलते खरीद सिर्फ 1.88 करोड़ टन ही हो पाई थी। आमतौर पर गेहूं की खरीद अप्रैल से मार्च के दौरान की जाती है। हालांकि इस बार केंद्र ने राज्यों को बाजार में फसल की आवक के आधार पर खरीद की अनुमति देने का फैसला किया है।

बता दें कि अधिकांश राज्यों में गेहूं की आवक मार्च के पहले पखवाड़े में शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों ने एक मार्च से गेहूं खरीद शुरू करने का संकेत दिया है।

शहरी सहकारी बैंकों को और सशक्त बनाने की तैयारी, अमित शाह करेंगे एनयूसीएफडीसी का उद्घाटन

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को इन बैंकों के अंब्रेला संगठन नेशनल अर्बन को-आपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन करेंगे। संगठन का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक एवं सशक्त करना है जिससे बैंकों के साथ ग्राहकों को भी लाभ होगा। अभी देश में 1500 से अधिक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक हैं।

नई दिल्ली। 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को अत्यधिक सशक्त बनाने की तैयारी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को इन बैंकों के अंब्रेला संगठन नेशनल अर्बन को-आपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन करेंगे।

1,500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक

संगठन का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक एवं सशक्त करना है, जिससे बैंकों के साथ ग्राहकों को भी लाभ होगा। संचार की सुविधा मिलेगी और चुनौतियों का समाधान होगा। अभी देश में 1,500 से अधिक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक हैं जिनकी कुल शाखाओं की संख्या 11 हजार से अधिक है।

इनके पास 5.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है। साथ ही इन्होंने 3.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण कर रखा है। इनमें से कई बैंक पुराने तरीके से काम करते हैं, जिससे नवीनतम सेवाएं नहीं मिल पाती हैं।

नई तकनीक में अपग्रेड कर रहे बैंक

अब एनयूसीएफडीसी का हिस्सा बनकर अधिकांश बैंक नई तकनीक में अपग्रेड करने और नए उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम होंगे। इस संगठन के जरिए शहरी बैंकों को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सहायता मिलेगी। लक्ष्य तीन सौ करोड़ रुपये के पूंजी आधार तक पहुंचना है।

पूंजी का उपयोग शहरी सहकारी बैंकों को समर्थन देने और सेवा पेशकशों में सुधार और लागत कम करने के लिए एक साझा प्रौद्योगिकी मंच विकसित करने में किया जाएगा।

दिल्ली में रेल पटरियों पर महीने में 45 लोग जान गवां देते हैं

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। राजधानी दिल्ली की उम्र से लम्बी रेल पटरियों को सडक की तरह इस्तेमाल करने वाले राहगीर अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर देते हैं। रेल सूत्रो के मुताबिक हफ्ते में करीब 11 से ज्यादा लोग जान गंवा देते हैं।

सूत्रो के मुताबिक ट्रेन की चपेट में आकर बीते साल भर में करीब 688 लोग अपनी जान गंवा चुके है।इनमें 51 महिलाए और 576 पुरूष शामिल है।अब अगर इस वर्ष की बात करे तो फरवरी,2024 तक 61 लोग ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गवां चुके है। इनमें महिलाओ की मौत का आंकडा 7 है और जान गंवाने वाले पुरूषों की संख्या 54 है। वहीं रेल चपेट में आने से विक्लांग होने वाले भी काफी है।

रेल पटरियों पर दौडती मौत के मामले अधिकतर बडे स्टेशनों पर रेल पटरियों को लांघ कर शॉट कट अपनाने वाले ज्यादा हैं। इन स्टेशनों में हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली कैंट,सब्जी मंडी, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली ,सराय रोहिल्ला,आनंद विहार प्रमुख हैं। वहीं मौत को देने वाले स्टेशनों में छोटे स्टेशन भी पीछे नहीं है। जहां सबसे ज्यादा हादसे गिनती में है। इनमें आदर्श नगर,नरेला,नांगलोई, शाहदरा, घेरा, बिजवासन,औखला, मंगोल पुरी, जैसे स्टेशन प्रमुख है। वहीं इन रेल हादसे में पुलिस महकमें के सूत्रों का कहना है कि ट्रेन की चपेट में आने वाले अधिकतर लोग रेलवे ट्रैक के दोनों ओर बसी झोपड पट्टिय है। रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले हजारों लोगों का रात बे रात रेल पटरियों पर आवागमन चलता रहता है। औधौगिक एरिया में काम करने वाले लोग इन्हीं रेल ट्रैक का इस्तेमाल पैदल आवागमन के करते हैं। काम पर जाते और लौटते वक्त वह रेल ट्रैक पर हादसे का शिकार बन जाते है। हालांकि इस बावत पुलिस महकमें के आलाधिकारी का कहना है कि पुलिस और रेलवे पुलिस मिलकर निरंतर का करते रहते हैं ।हादसे वाले क्षेत्रों को बाकायदा चिंहित किया जाता है। वहीं स्टेशन पर अनाऊंसमेंट कर सचेत करने,साइन बोर्ड लगाकर लोगों को सावधान किया जाता है। रेलवे अथॉरटी से रेलवे ट्रैक पर झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की सुरक्षा के तहत आवाजाही को रोकने के लिए तार लगाने और दिवार बनाने की लगातार सिफारिश करते हैं। लेकिन शॉट कट के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन हद है कि ट्रैक पर आवाजाही के लिए कोई रोक- टोक नहीं है। बस्तियों के आसपास फुटओवर ब्रिज बनाने चाहिए। वहीं रेलवे पटरियों के आस-पास किसी भी झुग्गी बस्ती को बसाने से पहले सख्ती से रोकना चाहिए। तभी रोज-ब-रोज रेलवे ट्रैक पर मरने वालों के हादसे पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा।

शीर्ष न्यायालय की मुहर: 2 से अधिक बच्चों वाले कैंडिडेट को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

राजस्थान में पंचायत चुनाव के साथ-साथ, सरकारी नौकरी के लिए भी अब 'दो बच्चों' की नीति अनिवार्य हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से यह नियम लागू हो गया है। अब वे उम्मीदवार जो दो से अधिक बच्चों वाले हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें यह नियम मानना होगा। इसे लेकर जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। वह 2017 में सेवा से रिटायर हो गए थे और उन्होंने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया, कहते हुए कि किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस नियम का उद्देश्य परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना है, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। न्यायमूर्ति कांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "कुछ इसी तरह का प्रावधान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में पेश किया गया था। उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में बरकरार रखा है। इसके तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था।"

1244 करोड़ रुपए से अपग्रेड होंगे नेशनल हाईवे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जारी की धनराशि

परिवहन विशेष न्यूज

शिमला। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग को अपग्रेड करने के लिए बजट का प्रावधान कर दिया है। केंद्र ने नेशनल हाईवे 205 के 1244.43 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सोलन और बिलासपुर जिलों में नेशनल हाईवे पर पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन को अपग्रेड किया जाएगा। इसका लाभ शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर कलार बाला गांव से नौणी चौक तक मौजूदा सडक़ को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 1244.43 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे में होने वाले इस सुधार का लाभ समूचे हिमाचल को मिलेगा। सोलन और बिलासपुर से कांगड़ा, मंडी या शिमला की तरफ जाने वाले लोग आसानी से बिना समय गंवाए अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार की इस सौगात से नेशनल हाईवे में और अधिक सुधार होने की संभावना है।

गौरतलब है कि नए साल में प्रदेश को मिली यह दूसरी सौगात है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नेशनल हाईवे को जोडने वाली सडक़ों को अपग्रेड करने के लिए 152 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुके हैं। केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के बाद बरसात के दौरान सडक़ों को हुए नुकसान में भी सुधार हो सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह फैसला दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात के बाद लिया था। इस धनराशि को पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ही उन सडक़ों पर खर्च किया जाएगा जो नेशनल हाईवे को जोड़ती हैं।

सडक़ में 1244.43 करोड़ से पेव्ड शोल्डर

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल के सोलन और बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर कलार बाला गांव से नौणी चौक तक मौजूदा सडक़ को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन में अपग्रेड करने के लिए 1244.43 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। यह मार्ग परियोजना शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला और मंडी को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। साथ ही दाड़लाघाट और ए स की कनेक्टिविटी भी सुधरेगी।

शिवलिंग के ऊपर बांधी जाने वाली मटकी को क्या कहते हैं, इसे कब और क्यों बांधते हैं?

हम कई बार शिवलिंग के ऊपर एक मटकी बंधी हुई देखते हैं, जिसमें से बूंद-बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता रहता है। ये दृश्य अक्सर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। इस परंपरा से जुड़ी कई बातें हैं, जिसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है।

खासकर वैशाख मास में शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरी मटकी बांधने की परंपरा है। इस मटकी से बूंद-बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता रहता है। वैशाख मास में ही ऐसा क्यों किया जाता है और इस परंपरा का क्या महत्व है। इससे जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। आज हम आपको इसी परंपरा से जुड़ी खास बातें बता रहे हैं, जो इस प्रकार है'

क्या कहते हैं इस मटकी को?

शिवलिंग को ऊपर जो पानी से भरी मटकी बांधी जाती है, उसे गलंतिका कहा जाता है। गलंतिका का शाब्दिक अर्थ है जल पिलाने का करवा या बर्तन। इस मटकी में नीचे की ओर एक छोटा सा छेद होता है जिसमें से एक-एक बूंद पानी शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहता है। ये मटकी मिट्टी या किसी अन्य धातु की भी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस मटकी का पानी खत्म न हो।

क्या है इस परंपरा से जुड़ी कथा?

धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले कालकूट नाम का भयंकर विष निकला, जिससे संसार में त्राहि-त्राहि मच गई। तब शिवजी ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। मान्यताओं के अनुसार, वैशाख मास में जब अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है जो कालकूट विष के कारण शिवजी के शरीर का तापमान में बढ़ने लगता है। उस तापमान को नियंत्रित रखने के लिए ही शिवलिंग पर गलंतिका बांधी जाती है। जिसमें से बूंद-बूंद टपकता जल शिवजी को ठंडक प्रदान करता है।

इसी से शुरू हुई शिवजी को जल चढ़ाने की परंपरा?

शिवलिंग पर प्रतिदिन लोगों द्वारा जल चढ़ाया जाता है। इसके पीछे ही यही कारण है कि शिवजी के शरीरा का तापमान सामान्य रहे। गर्मी के दिनों तापमान अधिक रहता है इसलिए इस समय गलंतिका बांधी जाती है ताकि निरंतर रूप से शिवलिंग पर जल की धारा गिरती रहे।

इस बात का रखें खास ध्यान

वैसाख मास में लगभग हर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर गलंतिका बांधी जाती है। इस परंपरा में ये बात ध्यान रखने वाली है तो गलंतिका में डाला जाने वाला जल पूरी तरह से शुद्ध हो। चूंकि ये जल शिवलिंग पर गिरता है इसलिए इसका शुद्ध होना जरूरी है। अगर किसी अपवित्र स्त्रोत से लिया गया जल गलंतिका में डालने से भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

अत: सफाई और शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है।

दिल्ली में पानी पर छिड़ी राजनातिक जंग, सेटलमेंट के मुद्दे पर AAP-LG आमने-सामने

दिल्ली वर्तमान में पानी के बिलों की वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। आप सरकार का कहना है कि ओटीएस को एलजी की ओर से अनुमति नहीं मिल रही वहीं भाजपा का कहना है कि बढ़े हुए बिल जल बोर्ड के नए मीटरों के कारण आ रहे हैं। आइए जानते हैं एलजी और सरकार के बीच के नूराकुश्ती की वजहें...

नई दिल्ली। कितना पानी चोरी हो रहा है, रिसाव में बर्बाद हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अनधिकृत कॉलोनियों में कैसे पानी की आपूर्ति हो रही है इससे भी किसी का सरोकार नहीं है। अभी तो सारा जोर वन टाइम सेटलमेंट पर है। कहानी जहां से 2013 में शुरू हुई थी, घूम फिरकर वहीं आती दिख रही है। उस समय भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी पानी के बिल, हवा से तेज भागते मीटर के मुद्दे के साथ मैदान में उतरी थी और अब एक बार फिर से लगातार बजट सत्र के नाम पर बीते 12 दिन से सदन में इसे ही लागू करने का विवाद गर्माया हुआ है।

ऐसे में सवाल ये उठता है कि पानी के नए मीटरों के कारण यदि बिल बढ़े आ रहे हैं तो मीटर क्यों नहीं बदले जा रहे? जल बोर्ड में निजीकरण की एंट्री हुई थी तो उस काम में परफेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसमें घपले क्यों उजागर हो गए? आखिर मीटर बदलने में कहां बाधा है? साथ ही, वर्तमान में सभी पहलुओं को देखते हुए इस मुद्दे का क्या है समाधान? कैसे दी जाए दिल्लीवासियों को इस परेशानी से राहत? इसी की पड़ताल करना हमारा आज का मुद्दा है।

दिल्ली वर्तमान में पानी के बिलों की वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। आप सरकार का कहना है कि ओटीएस को एलजी की ओर से अनुमति नहीं मिल रही, वहीं भाजपा का कहना है कि बढ़े हुए बिल जल बोर्ड के नए मीटरों के कारण आ रहे हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने लोगों का पानी मुफ्त कर रखा है तो ओटीएस स्कीम लाने के बजाय उसे सारे बिल शून्य घोषित कर देने चाहिए। आइए समझते हैं दिल्ली के पानी का जमा-गणित:

- क्या आप मानते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पानी के बढ़े बिलों के निपटारे का उचित समाधान है?

हां : 11
नहीं : 89

- क्या लोगों को बढ़े बिलों से निजात दिलाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को मीटर तत्काल बदलने चाहिए?

हां : 92
नहीं : 8

इसलिए आया अधिक बिल

दिल्ली सरकार का कहना है कि कई लोगों को निश्शुल्क जल योजना के स्वतः लागू होने और पिछली योजना के तहत बकाया राशि की 100% छूट के बारे में गलतफहमी थी। पानी मीटर रीडरों द्वारा मीटर रीडिंग गलत पंच करने की भी कई शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा, कोरोना काल में लाकडाउन के कारण मीटर रीडिंग भौतिक रूप से नहीं की जा सकी। इसलिए, पानी के मीटरों की भौतिक रीडिंग के अभाव में बिल औसत रीडिंग (अर्थात प्रति माह 25 किलोलीटर उपयोग) के आधार पर बनाए जा रहे थे। पिछले बकाया और वर्तमान बिलों में जोड़ा गया विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएससी) से पानी का बिल अधिक हो गया।

ओटीएस योजना

वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत उपभोक्ता का बिल फिर से तैयार किया जाएगा। यदि उपभोक्ता इस राशि का भुगतान करता है तो पूरा बकाया समायोजित कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता को एक लाख रुपये का बढ़ा हुआ बिल मिला है और उसके पानी के उपभोग के आधार पर बिल को सात हजार रुपये कर दिया जाता है (रीकास्ट बिल) तो उसे इस राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। अगले बिलिंग चक्र से उसे नया बिल मिलेगा। रीकॉस्टिंग राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे एक लाख रुपये का भुगतान करना होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता के पास चार माह का समय होगा।

- दो तरह से है मौका

- प्रथम श्रेणी: पिछले एक वर्ष में दो सही रीडिंग वाले बिल के आधार पर उनका दोबारा बिल तैयार किया जाएगा। पिछले एक वर्ष की दो सही रीडिंग प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने वाले उपभोक्ताओं की रीडिंग की गणना पिछले पांच वर्षों के आधार पर की जाएगी।

- द्वितीय श्रेणी: यदि खराब मीटर या बिल की समस्या पांच वर्ष से अधिक पुरानी है तो उपभोक्ता के पड़ोस के पानी उपभोग के आधार पर बिल तैयार किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की 100% एलपीएससी माफ कर दिया जाएगा।

खराब मीटरों में भी हो जाएगा सुधार

दिल्ली सरकार के अनुसार ओटीएस योजना उन सभी उपभोक्ताओं को दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत लाने में मददगार साबित होगी जिनके पानी के मीटर खराब हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को खराब मीटर को बदलवाना होगा। इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलने के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड का राजस्व बढ़ेगा।

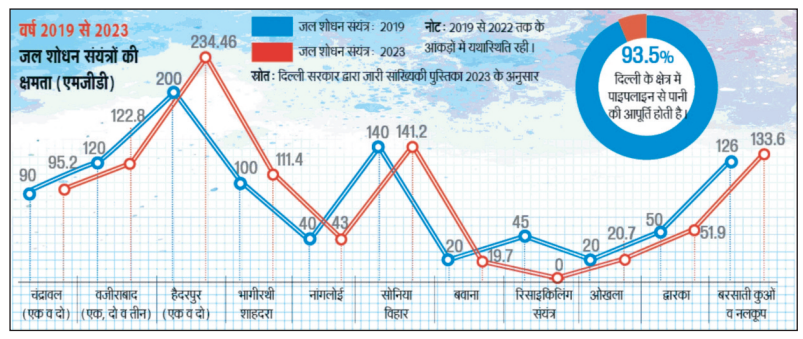

पानी का बिल बढ़कर आने के कारण कई उपभोक्ता उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं जिससे जल बोर्ड को नुकसान हो रहा है। इस योजना से जल बोर्ड को लगभग 2,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर मंत्री के निर्देश के बाद शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस योजना को कैबिनेट में लाने से इनकार कर दिया।

वोट बैंक की राजनीति में अटक रहा पानी का बिल निपटारा

दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व तकनीकी सदस्य आरएस त्यागी के मुताबिक दिल्ली में पानी के बकाए बिल के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट की योजना सुर्खियों में है। सरकार अधिकारियों व उपराज्यपाल पर इस योजना को रोकने का आरोप लगा रही है। यही बात यह है कि मुफ्त पानी योजना से दिल्ली जल बोर्ड की आर्थिक सेहत अच्छी नहीं है। यदि जल बोर्ड और सरकार टाइम सेटलमेंट की योजना लाना चाहती है या जल बोर्ड पानी का मीटर बदलना चाहे तो इसमें कोई अड़चन नहीं है। ताजा मामला राजनीतिक है।

उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में योजना लटक रही है। वैसे बकाया बिल के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट समस्या का निदान नहीं है। इससे जल बोर्ड का आर्थिक घाटा और बढ़ेगा। इससे भविष्य में समस्याएं अधिक बढ़ सकती हैं।

रीडिंग लेने के लिए निजी कंपनियों को ठेका

यदि बकाया बिल पर उपभोक्ताओं को राहत देनी ही है तो पहले राहत क्यों नहीं दी गई। पिछले वर्ष ही इसे लागू करने की बात कही गई थी। फिर इसे उस वक्त यह योजना क्यों लागू नहीं की गई और यदि अधिकारियों की तरफ से कोई अड़चन थी तो उसी वक्त मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? चुनाव नजदीक मुद्दा उठाना राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है।

उन्होंने कहा कि जल बोर्ड पानी के मीटर की रीडिंग लेने के लिए निजी कंपनियों को ठेका दिया है। मीटर रीडर को बाकायदा टैबलेट दिए गए हैं। उन्हें मीटर रीडिंग का फोटो वीडियो लेकर अपलोड करना होता है। ऐसे में यह गंभीर सवाल है कि पानी के बिल गलत कैसे तैयार हुए? यदि पानी का बिल गलत बना तो इसके लिए जल बोर्ड और वह निजी एजेंसियां जिम्मेदार हैं जिसकी सेवाएं जल बोर्ड ले रहा है।

ज्यादातर उपभोक्ताओं के यहां पानी के पुराने मीटर

जल बोर्ड ने उन कांट्रैक्टर्स का बिल भुगतान भी जारी रखा है। यदि बिल गलत बन रहे तो निजी कांट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और उनका बिल भुगतान रोक देना चाहिए था। मौजूदा समय में जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं वे सत्ता में आने से पहले कहा करते थे कि फूंक मारो तो पानी का मीटर तेज भागता है।

उन्होंने कहा कि ज्यादातर उपभोक्ताओं के यहां पानी के पुराने मीटर ही लगे हुए हैं। आठ-नौ वर्ष पहले पानी के मीटर बदलने के लिए दो कंपनियों को कांट्रैक्ट दिए गए थे। एक-एक कंपनी को चार-चार लाख घरों में मीटर लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसलिए आठ लाख उपभोक्ताओं के मीटर बदले भी गए थे।

शर्तों के मुताबिक पानी के मीटर वारंटी पांच वर्ष थी। जिसे पांच वर्ष के अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया भी गया था। इसलिए पानी के मीटर पर कुल दस वर्षों की वारंटी थी। यदि नए लगे ये मीटर तेज भाग रहे हैं तो उसे ठीक कराया जाना चाहिए था या उसे अब बदल दिया जाना चाहिए था।

दिल्ली जल बोर्ड के करीब 27 लाख उपभोक्ता

उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के करीब 27 लाख उपभोक्ता हैं। करीब 11 लाख उपभोक्ताओं का बिल बकाया होने की बात कही जा रही है जिसके लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाने की योजना सुर्खियों में बनी हुई है। इसका मतलब है कि करीब 40% उपभोक्ता पानी का बिल नहीं भर रहे हैं।

बाकी उपभोक्ता नियमित पानी का बिल भर रहे हैं। जब-जब चुनाव नजदीक आता है तब बिल माफ करने की बात सामने आती है। सवाल यह है कि बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं का यदि बिल माफ कर दिया जाएगा तो उन उपभोक्ताओं की क्या गलती है जो नियमित बिल भर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि क्या नियमित बिल भरने वाले उपभोक्ताओं का पैसा भी वापस किया जाएगा? क्योंकि बिल तो उनके भी गलत हो सकते हैं। इसलिए मामले की जांच कराई जानी चाहिए। यदि सरकार पानी का मीटर बदलना चाहे या वन टाइम सेटलमेंट योजना लाना चाहे तो इसमें कोई खास अड़चन नहीं है।

जल बोर्ड की बोर्ड बैठक में योजना को स्वीकृति दिलाकर कैबिनेट में रखा जा सकता है। यदि अधिकारी इसे कैबिनेट में रखने में आनाकानी कर रहें तो सरकार स्वतः कैबिनेट में इसे रख सकती है। शीला दीक्षित कई योजनाओं को इस तरह से लागू कराया था।

भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें ओटीएस से कुछ नहीं होगा

सिटीजंस फ्रंट फार वाटर डेमोक्रेसी के संयोजक एसए नकवी ने बताया कि साल 2013 में शुद्ध जल आपूर्ति, उपभोक्ताओं को भेजे गए गलत बिल, गलत रीडिंग राजनीतिक मुद्दा बना था। आम आदमी पार्टी ने इस समस्या को जोरशोर से उठाया था। इस विषय को उठाकर वह सत्ता तक पहुंची थी।

इन समस्याओं का समाधान करना उसका कर्तव्य है, परंतु स्थिति नहीं सुधरी है। दुर्भाग्य से 11 वर्ष बाद 2024 में भी यह राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। कहा जा रहा है कि 11 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के गलत बिल भेजे गए हैं।

उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह सही नहीं है। इस समस्या का मुख्य कारण दिल्ली जल बोर्ड के काम को निजी हाथों में देना है। उपभोक्ताओं से बिल वसूलने का काम निजी हाथों में दे दिया गया है। उनके ऊपर किसी तरह की निगरानी नहीं है। बिल वसूलने व अन्य काम में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जल बोर्ड के कई अधिकारी पकड़े गए हैं। जल बोर्ड के निजीकरण का दुष्परिणाम सभी के सामने हैं।

राघव चड्ढा के सामने गलत बिल का मामला

नकवी ने कहा कि उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजने का मामला उजागर होने के बाद भी दिल्ली जल बोर्ड व दिल्ली सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वर्ष 2021 में दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन उपाध्यक्ष राघव चड्ढा के सामने गलत बिल का मामला आया था। अगस्त, 2022 में जल बोर्ड के तत्कालीन उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गलत रीडिंग लेने वाले मीटर रीडरों व संबंधित निजी कंपनियों के विरुद्ध एफआइआर के आदेश दिए थे। यदि पिछले तीन वर्षों में उपभोक्ताओं को भेजे गए गलत बिल की समस्या का समाधान हो जाता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

उन्होंने कहा कि यह निजी कंपनियों के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है इसलिए इसका समाधान वन टाइम सेटलमेंट योजना से नहीं होगा। दिल्ली जल बोर्ड के पास उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण करने की व्यवस्था है। प्रश्न यह उठता है कि इस व्यवस्था को ठप क्यों किया जा रहा है?

उपभोक्ताओं द्वारा गलत बिल की शिकायत करने पर उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? इस तरह की लापरवाही व भ्रष्टाचार के कारण उपभोक्ता परेशान हैं। वह बिल ठीक कराने के लिए जल बोर्ड के कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। अब चुनाव का समय नजदीक आने पर यह मामला उठ रहा है। इस विषय पर राजनीति करने की जगह इसके समाधान पर ध्यान देने की जरूरत है।

जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति और होगी खराब

उपभोक्ताओं को अधिक व गलत बिल भेजे जाने के कारण वह भुगतान नहीं कर रहे हैं। इससे जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति और खराब होगी जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसे गंभीरता से लेते हुए समाधान का रास्तान निकालना होगा। इसके लिए सबसे पहले गलत बिल भेजने वाली निजी कंपनी की जिम्मेदारी तय करनी होगी। उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच से इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सकेगी। कानूनी कार्रवाई के साथ ही उपभोक्ताओं को भेजे गए गलत बिल को सुधारने के लिए अविलंब काम शुरू करना होगा। दिल्ली जल बोर्ड के लिए यह काम मुश्किल नहीं है। गलत बिल की समस्याओं का समाधान पहले भी होता रहा है, फिर इस बार इसे क्यों लटकाया जा रहा है? इस विषय पर राजनीति करने की जगह उपभोक्ताओं व दिल्ली जल बोर्ड के हित में कदम उठाने की जरूरत है अन्यथा परेशानी और बढ़ेगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023